



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 1, 1982/फाल्गुन 10, 1903
No. 40] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 1, 1982/PHALGUNA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

बजट अनुभाग
बजट 1982-83

वित्त मंत्री का प्रावण
नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1982

भाग—क

पत्र सं० बि० म० (ई०ए०सी०) यू०ओ०सं०फा० 15(4)-बी०(डी०)/82

महोदय,

मैं वर्ष 1982-83 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

2 कुछ दिन पहले, वर्ष 1981-82 की "आर्थिक समीक्षा" सदन के सम्मुख प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों का विस्तृत विवेचन किया गया था। अतः मैं आर्थिक स्थिति के कारण उन कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का संक्षेप में उल्लेख करूँगा जिन्होंने इस वर्ष के बजट पर प्रभाव डाला है।

3. जैसाकि सदन को मालूम है, जब दो वर्षों से कुछ अधिक समय पूर्व वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला था, उस समय देश की आर्थिक स्थिति बड़ी गंभीर और बिगड़ी हुई थी। 1979-80 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 4.8 प्रतिशत की गिरावट आ गई थी, आयातभूत ढाँचे की हालत बड़ी खस्ता थी और जनवरी 1980 के अस्त तक कीमतें 23.3 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ गई थीं। यह थी वह पृष्ठभूमि जिसमें मेरे सुप्रतिष्ठित पूर्ववर्ती वित्त मंत्री ने 1980-81 का नियमित बजट प्रस्तुत करते हुए सदन को सूचित किया था कि सरकार के सम्मुख जो अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य हैं वह यह है कि आर्थिक स्थिति को बिगड़ने से रोका जाए और अर्थ-व्यवस्था को स्थिरता तथा विकास के मार्ग पर अग्रसर किया जाए।

4. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने बहुत हद तक ये उद्देश्य पूरे कर लिये हैं। वास्तविक अर्थों में हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, 1980-81 में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 1981-82 में इसमें 4.5 प्रतिशत की और वृद्धि होने की संभावना है। आयातभूत ढाँचा ठीक तरह से काम कर रहा है। मुद्रास्फीति पर काबू पाया जा रहा है। भाषा है कि इस वर्ष अनाज का उत्पादन एक नए शिखर पर पहुँच जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में 8 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

5. मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई को सरकार ने उच्च प्राथमिकता दी है। यदि इस मोर्चे पर किए जाने वाले प्रयासों में कोई ढील दी जाती तो इससे हमारे विकास की बुनियाद ही हिल जाती। मुद्रास्फीति ने समाज के सभी वर्गों को काष्ट पहुँचा है, लेकिन इससे सबसे अधिक तकलीफ समाज के कमजोर और गरीब वर्गों को होती है। मुद्रास्फीति से विकास की प्रक्रिया को धक्का लगता है क्योंकि उससे निवेश की लागत विकृत हो जाती है और वित्त पोषण अधिकाधिक संभरी समस्या बन जाता है। अतः यह संतोष की बात है कि हमने मुद्रास्फीति की दर को काफी हद तक कम करने में सफलता प्राप्त कर ली है।

6. जनवरी 1982 के अंत में बिन्दु-प्रति बिन्दु आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर केवल 4.9 प्रतिशत थी, जबकि इसकी तुलना में जनवरी 1981 के अंत में यह 15.9 प्रतिशत और जनवरी 1980 के अंत में, जब वर्तमान सरकार ने सत्ता संभाली थी, यह 23.3 प्रतिशत थी। कई वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है और धीरे-धीरे यह गिरावट उपभोक्ता कीमतों के सूचक अंक में परिलक्षित होने लगी है।

7. लेकिन कीमतों की स्थिति पर बराबर तजर रखने की जरूरत है और हम संबंध में हाथ पर हाथ रखकर बैठने की कोई गंजाइश नहीं है। विदेशों में कीमतों की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। देश में स्थिति यह है कि एक बार सूखा पड़ने से या किसी एक बड़ी फसल के खराब हो जाने से मांग और पूर्ति का संतुलन बिगड़ सकता है। अतः हमें कृषि वस्तुओं तथा औद्योगिक वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाने और समूची मांग की वृद्धि को काबू में रखने के लिए भी अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा। साथ ही साथ हमें इस बात की मुनिश्चित व्यवस्था करनी होगी कि समाज-विरोधी तत्व पूर्ति की स्थिति और वितरण की व्यवस्था में रुकावट पैदा न कर सकें।

8. जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, चालू वर्ष में अनाज का उत्पादन नए शिखर पर पहुँच जाने की संभावना है। अनुमान है कि खरीफ के अनाजों का उत्पादन लगभग 800 लाख मेट्रिक टन होगा, जबकि इसकी तुलना में 1980-81 में यह 774 लाख मेट्रिक टन था और रबी की फसल की संभावनाएँ भी बहुत अच्छी हैं। आशा है कि गन्ने के उत्पादन में काफी अधिक वृद्धि होगी और चीनी का उत्पादन 67 लाख मेट्रिक टन से भी अधिक के रिकार्ड स्तर पर पहुँच जाएगा। मूंगफली का उत्पादन भी पिछले वर्ष की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत अधिक होगा। कपास और जूट के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।

9. कृषि-क्षेत्र के उत्पादन में जो लगातार वृद्धि हो रही है, वह हमारे किसानों, कृषि-वैज्ञानिकों और विस्तार कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का सबूत है। इससे यह बात भी सिद्ध होती है कि हमारी कृषि नीति बुनियादी तौर पर सही है जिसमें सिंचाई क्षमता के निर्माण, उर्वरकों के अधिकाधिक उपयोग, अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों के प्रसार और लाभप्रद मूल्य समर्थन नीतियों पर जोर दिया गया है।

10. वर्ष 1979-80 में औद्योगिक उत्पादन 1.4 प्रतिशत घट गया था, लेकिन 1980-81 में इसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1981-82 में वृद्धि की यह दर इससे दुगुनी होगी। आशा है कि वर्ष के दौरान पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बनावट, कीमती, अन्नबारी कागज, कास्टिक सोडा, बैगन और वाणिज्यिक गाड़ी जैसे कई उद्योगों का उत्पादन नए शिखरों पर पहुँच जाएगा। सरकार ने आधारभूत क्षेत्रों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो ठोस कार्रवाई की है उसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि को बराबर कायम रखा जा सका है। चालू वित्तीय वर्ष में, जनवरी तक विद्युत उत्पादन में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले दो वर्षों में कोयले के उत्पादन में 170 लाख मेट्रिक टन से भी अधिक की वृद्धि हुई है और आशा है कि 1981-82 में कोयले का उत्पादन 1210 लाख मेट्रिक टन के लक्ष्य से भी बढ़ जाएगा। रेलवे द्वारा की जाने वाली माप की लाई पिछली

रिकार्ड दुलाई से भी अधिक होगी और रेलवे का राज्य उपाजक यातायात अर्थात् रेलवे अतिरिक्त ट्रैफिक भी बढ़कर 165 अरब मेट्रिक टन किनामीटर हो जाएगा। वर्ष के दौरान रेलों की परिचालन क्षमता में सुधार करके, उदाहरण के तौर पर, वेगनों के वापस आने के समय में काफी कमी कर के हो ऐसा करना संभव हो सका है।

11. वर्ष के दौरान मौद्रिक और ऋण नीतियों में अधिक उत्पादन के लिए, विशेषकर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और इसके साथ-साथ समूची मांग में वृद्धि को काबू में रखने पर जोर दिया जाता रहा। अर्थ-व्यवस्था में नकदी के प्रसार को नियंत्रण में रखने के लिए नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात को विभिन्न चरणों में 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया और सांघिक नकदी अनुपात को 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया। बैंक दर को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया और भारतीय रिजर्व बैंक की पुनर्वित्त को दर भी बढ़ा दी गई। इसके बावजूद, 1981-82 में, वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋण में 19 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने की संभावना है, जो उत्पादक क्षेत्रों को ऋण संबंधी उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

12. सम्मानित सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंकों के क्रियाकलापों में इस बात पर और अधिक जोर दिया जा रहा है कि उन ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाए जहाँ पहले ये सुविधाएँ कम हैं और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को पहले से अधिक ऋण दिए जाएँ। जनवरी—नवम्बर, 1981 में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 2517 नई शाखाएँ खोली गईं जिनमें से 2269 शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में खोली गईं थीं। 1980 के अंत में क्षेत्रीय प्रमाण बैंकों की संख्या 85 थी। 1981 में 22 ऐसे और बैंक खोले गए। समूचे बैंक ऋण का लगभग 36 प्रतिशत हिस्सा अब प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को मिलता है, जबकि 1979 में यह हिस्सा 33 प्रतिशत था। मार्च 1985 तक इस हिस्से को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्याज की विशेषी बरों की योजना अर्थात् डिफेंसिवल रेट प्राँक इंटेस्ट स्कीम बड़े कारगर ढंग से प्रयत्न में लाई गई है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है जिससे इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण बैंकों के समूचे ऋण के 1 प्रतिशत के बराबर हों। आशा है अगले कुछ महीनों के अन्तर-अन्तर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अपना कार्य शुरू कर देगा। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पहली जनवरी, 1982 से भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना की जा चुकी है।

13. अब मैं भुगतान-शेष की स्थिति का जिक्र करना चाहूँगा। जैसा कि सदन को मालूम है, मुख्यतः आयात की कीमतों में, विशेषकर तेल और तेल उत्पादों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो जाने के कारण, 1979-80 से हमारे भुगतान-शेष की स्थिति काफी बिगड़ गई। इन घटनाओं का पूर्वानुमान लगा कर, सरकार ने, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित सुविधा (एक्सटेंडिड फेसिलिटी) के अंतर्गत 5 अरब एस डी ड्रार के एक ऋण के लिए बातचीत करने का समय पर प्रबंध किया। ऐसा करना इस लिए जरूरी था कि आयात को जाने वाली अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी के कारण हमारी अर्थ व्यवस्था में कोई रुकावट न आए और नई स्थिति के अनुसार अपने आप को फिर से डालने के लिए हमें समय मिल जाए। यह ऋण लेना हमारे स्वीकार किया गया है कि योजनाबद्ध विकास की हमारी नीति के समायोजन कार्यक्रम को समर्थन प्रदान किया जा सके। इस ऋण से हमें अपनी उन नीतियों को प्रयत्न में लाने में सहायता मिलेगी, जिन्हें हमारी जनता और संसद अपनी स्वीकृति तथा अपना अनुमोदन प्रदान कर चुकी हैं।

14. आने वाले वर्षों में हमारे भुगतान-शेष की स्थिति को फिर से संतुलित बनाने की सरकार की नीति का मुख्य तत्व है: सर्वप्रथम देश में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, इस्पात, खाद्य तेलों और अलौह

आयुधों का उत्पादन बढ़ाना। ये वस्तुएं हमारे कुल आयात का लगभग 60 प्रतिशत बैठती हैं। इन क्षेत्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने और पूंजी निवेश में वृद्धि करने के लिए सरकार ने आवश्यक कार्रवाई की है।

15. इसके साथ-साथ हमें अपने निर्यात के आधार का विस्तार करने और अधिकाधिक निर्यात के अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करने की दिशा में अपने प्रयत्नों को तेज करना होगा। वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों में निर्यातों में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो उत्साहजनक है। लेकिन, कई क्षेत्रों में, विशेषकर सूती कपड़े, जूट और चाय जैसे हमारे परंपरागत निर्यातों के मामले में हमें विश्व के बाजारों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इन निर्यातों और अन्य परंपरागत वस्तुओं के निर्यातों के स्तर को कायम रखते हुए उन निर्यातों को बढ़ाने के लिए अब पहले से अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है जिनके लिए विश्व के बाजारों में मांग में वृद्धि हो रही है। हाल के वर्षों में, अशुभ भयों से होने वाली हमारी आप्तियों में विशेषकर भारतीय मूल के अधिवासियों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशियों में काफी वृद्धि हुई है। हमारे भुगतान-शेष की स्थिति को स्थिरता प्रदान करने वाला यह एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है और इस स्रोत से होने वाली आप्तियों में वृद्धि करने के लिए हमें पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करते रहना चाहिए।

16. पिछले दो वर्ष अर्थ-व्यवस्था के संकट का मुकाबला करने और उसमें सुधार लाने के वर्ष रहे हैं। यह हमारी सफलता का सूचक है कि अर्थ-व्यवस्था फिर से सही रास्ते पर आ गई है। इससे हमें अर्थ-व्यवस्था को आगे बढ़ाने और आवश्यक मध्यावधि समायोजन करने के लिए और प्रयत्न करने का अवसर प्राप्त हुआ है। 1982-83 में नीति का उद्देश्य यह होगा कि विकास की गति को कायम रखा जाए और छठी आयोजना के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी उपाय किए जाएं। ऐसा करने के प्रयोजन से पहले से अधिक पूंजी-निवेश करना होगा और अधिक उत्पादकता, कार्यकुशलता तथा विषमताओं को कम करने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। संशोधित 20-सूची कार्यक्रम का यही संदेश है। इस कार्यक्रम में वे क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं जहां विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जिनके कार्य और निष्पादन में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए।

17. हमें जो काम करने हैं, वे आसान नहीं हैं। सम्मानित सदस्य भली भांति जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में कैसी भौगोलिक-राजनीतिक स्थिति पैदा हो रही है और हम कितने कठिन समय में काम कर रहे हैं। यद्यपि हम सद्भावना के साथ स्थिति को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हर सम्भव उपाय करना जरूरी है। यह बोझ हमने जानबूझ कर अपने ऊपर नहीं लिमा है और इसके लिए हमारी जनता को त्याग करना होगा।

18. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में, संरक्षण को प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जो विदेशी बाजारों में हमारी पहुंच के मार्ग में बाधा उपस्थित करती है। आर्थिक सहयोग का वातावरण भी बिगड़ा है और पहले रियायती शर्तों पर जितने साधनों की प्राप्ति की परिकल्पना की गई थी, अब उस से कम साधन प्राप्त होने की संभावना है। अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर हमें अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए और इन जिता-जनक प्रवृत्तियों को बदलने के लिए दबाव डालते रहना चाहिए लेकिन अर्थ-व्यवस्था के विवेकपूर्ण प्रबंध के लिए यह जरूरी है कि अपनी आर्थिक नीतियां तैयार करते समय हम वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का यथोचित ध्यान रखें।

19. अर्थ-व्यवस्था के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकताएं बहुत बड़ी हैं और इसके लिए अब कोई देर नहीं होनी चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अब पूंजी निवेश के लिए अधिक साधन जुटाने के बास्ते ढूँढ

प्रयास करें। गैर-मुद्रास्फीतिकारी वातावरण बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि अर्थ-व्यवस्था में जो अतिरिक्त साधन जुटाए जाएं वे वास्तविक बचतों में से ही जुटाए जाएं। लेकिन नई श्रमताओं में अतिरिक्त पूंजी निवेश के लिए पर्याप्त साधन तब तक उपलब्ध नहीं होंगे जब तक हम वर्तमान श्रमताओं का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए भी कार्रवाई नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह सबन इस आशा में मेरा साथ देगा कि इस उत्पादकता वर्ष को सफल बनाने में समाज के सभी वर्ग भरमक प्रयत्न करेंगे। सरकार अपनी ओर से इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए यथोचित प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रयास करेगी।

20. गैर-मुद्रास्फीतिकारी रूप में साधनों का जुटाया जाना निश्चय ही एक बहुमुखी प्रयास होना चाहिए। इस काम के लिए कराधान में उचित समायोजन करना और करों से अधिक प्राप्ति सुनिश्चित करना जरूरी है। अर्थ-व्यवस्था में काले धन की जो घातक वृद्धि हुई है, वह सरकार और संसद दोनों के लिए भारी चिंता का विषय है। विभिन्न आर्थिक अपराधों ने हमारे विकास प्रयासों का गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई है। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए गत वर्षों में हमने कई उपाय किए थे। दुर्भाग्यवश, जब हम सत्ता में नहीं रहे थे तब इन प्रयासों में छिलाई आ गई थी। मैं सम्मानित सदस्यों को यह विश्वास दिलाता चाहता हूँ कि सभी आर्थिक अपराधों को जड़ से उखाड़ फेंकने को हमारी वचनबद्धता बिल्कुल अनुप्राण है और इस संबंध में किसी प्रकार के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ऐसे उपाय करने जा रहा हूँ जिनसे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था हो सके कि आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए कानून के उपबंधों का बड़े जोर के साथ और कारगर ढंग से अनुपालन किया जाए।

21. हमें आर्थिक लागतों के अनुकूल निर्देशित कीमतों में भी बराबर समायोजन करते रहना चाहिए। सरकारी क्षेत्रों और उच्च प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों में अलाभप्रद मूल्य नीतियों के कारण और आगे पूंजी निवेश के लिए साधनों का ह्रास हो जाता है और इस से सिद्धांतहीन व्यापारियों को कदाचर का मौका मिल जाता है। पिछले दो वर्षों में कीमतों में जो समायोजन किए गए हैं उनसे वह भली भांति सिद्ध हो गया है कि सक्षम कार्य संचालन अतिरिक्त साधनों के निर्माण और काले धन के पैदा होने को अशुभ-सुरों को कम करने में उचित मूल्य नीतियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है।

22. हमारी अर्थ-व्यवस्था की एक बड़ी ताकत यह है कि हमारी बचत का दर अपेक्षाकृत काफी ऊंची है अधिकांश बचतें परिवारिक क्षेत्र की बचतें होती हैं। हमारे लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बचतकर्ताओं को वित्तीय प्रतिभूतियों में अपनी बचतों को लगाए रखने में पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो। यह बात निवेश के लिए अधिक रकमें जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। पिछले दो वर्षों में, इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। यह प्रयास जारी रहना चाहिए।

23. निजी बचतों को सरकारी इस्तेमाल के लिए जुटाने के उद्देश्य से, सरकार ने दो नए बचत-पत्र जारी करने का फैसला किया है। पहला है, सामाजिक सुरक्षा पत्र जो विशेष रूप से अल्पबचतकर्ताओं के लिए है। इस स्कीम के अन्तर्गत, 18 और 45 वर्ष के बीच की आयु वाले व्यक्ति 5,000 रुपये तक की पूंजी लगा सकते हैं। जो दम वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। इस सुरक्षा पत्र से निवेशकर्ता के परिवार का सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होगी। उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उसके द्वारा नामजब व्यक्ति को अथवा उसके कानूनी उत्तराधिकारी को सुरक्षा पत्र के पूर्ण परिपक्वता मूल्य को प्राप्त करने का तत्काल अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इस स्कीम के व्योरे की घोषणा अलग से की जाएगी। मुझे विश्वास है कि ये राष्ट्रीय बचत-पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बहुत से लोगों और हर स्थान के कम आमदनी वाले लोगों के लिए विशेष रूप से आकर्षक सिद्ध होंगे।

24. दूसरा बचतपत्र पूंजी निवेश बांड है, जिसका उद्देश्य सरकारी क्षेत्र में निवेश के लिए निजी बचतों को अधिक मात्रा में आकर्षित करना है। इन बांडों की परिपक्वता की अवधि दस वर्ष की होगी और इन पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा जो आय-कर से मुक्त होगा। उन्हें धन कर से और प्रथम बांडधारी के मामले में 10 लाख रुपये तक दान कर से भी छूट प्राप्त होगी। खरीदारों को इन बांडों में लगाई गई पूंजी का सम्यक रूप से लेखा रखा होगा।

25. हम बचत की जो दर प्राप्त करने में सफल हुए हैं, उसका श्रेय हमारी जनता की मितव्ययता की भावना और सूक्ष्मता को जाता है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि बचतों को बढ़ावा देने के लिए नए अवसर और प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं, लोग उनका पूरा-पूरा लाभ उठाएंगे।

26. विदेशों से भेजी जाने वाली राशियां, देश के लिए विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये इस देश के लोगों और विदेशों में बसने वाले भारतीय मूल के लोगों के बीच विद्यमान घनिष्ठ सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों की भी छोटक हैं। इस स्रोत से धन की प्राप्ति को और प्रोत्साहन देने के लिए, अनिवासियों को उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि करने का फैसला किया गया है।

27. भारतीय मूल के अनिवासियों द्वारा प्रत्यावर्तन अधिकार के बिना, किये गए किसी भी पूंजी-निवेश को, निवासी भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा किए गए निवेश के समान समझा जाएगा, जब तक कि यह निवेश वाणिज्यिक संपत्ति अथवा भूमि के लेनदेन के लिए न किया गया हो। उन्हें किसी नई अथवा मौजूदा कंपनी में, उस कंपनी द्वारा जारी की गई पूंजी के 40 प्रतिशत तक का निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। अब वे शेयर बाजारों में कंपनियों के सूचीबद्ध शेयर, निर्धारित सीमाओं तक, खरीद सकते हैं। अनिवासियों के विदेशी खातों में, एक वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता अवधि वाली नई जमा राशियों के ब्याज की दर, तुलनीय परिपक्वता अवधि वाली स्थानीय जमा राशियों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर से 2 प्रतिशत ऊंची होगी। इन विदेशी खातों में जमा राशियों में से भारत में दिए जाने वाले उपहारों पर दान कर नहीं लगेगा। अनिवासी 12 प्रतिशत ब्याज वाले 6-वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्रों में भी पूंजी लगा सकते हैं। जो उनके मामले में, धन कर, आय कर और दान कर से मुक्त होंगे। अनिवासी विदेशी खातों में और भारतीय कंपनियों में निवेश की सुविधाएं उन कंपनियों, भागीदारी फर्मों, न्यातों, सांसाधनियों और अन्य निगमित निकायों को भी दी जाएंगी, जिनकी कम से कम 60 प्रतिशत तक मिलकियत भारतीय मूल के अनिवासियों के हाथ में होगी।

28. अब मैं 1981-82 के संशोधित अनुमानों और 1982-83 के बजट अनुमानों को लूंगा।

1981-82 के संशोधित अनुमान

29. मुझे सबन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1981-82 के दौरान राजस्व-प्राप्तियों में हर तरफ से वृद्धि हुई है। यह संतोष का विषय है कि 1981-82 के बजट में करों में भारी रियायतें दिए जाने के बावजूद आयकर से 1,520 करोड़ रुपये की प्राप्तियां होने की संभावना है। जबकि बजट में 1,444 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था। इसी प्रकार, संशोधित अनुमानों के अनुसार निगम कर से 1,962 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी, जबकि बजट में 1,690 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने का अनुमान था। इस वृद्धि का कारण यह है कि पिछली जूलाई में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि किए जाने से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया को अधिक मुनाफे हुए हैं। संशोधित अनुमानों के अनुसार सीमा शुल्कों से भी अधिक अर्थात् 4,140 करोड़ रुपये की प्राप्त होने की संभावना है, जबकि बजट 3,833 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था।

30. जहां तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संबंध है, सबन को यह जान-कर प्रसन्नता होगी कि उत्पाद शुल्क संग्रह 7,117 करोड़ रुपये से बढ़कर

7,501 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है, अर्थात् उसमें 384 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इससे चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में उत्प्रेक्षणीय वृद्धि होने का स्पष्ट संकेत मिलता है। अब अनुमान है कि 14,668 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में 15,754 करोड़ रुपये का सकल कर राजस्व प्राप्त होगा। अनुमान है कि विभिन्न करों में राज्यों के हिस्से को घटाने के बाद, केन्द्र का निवल कर राजस्व 10,537 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों से 943 करोड़ रुपये अधिक होगा।

31. कर-मिश्र राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में भी 12,795 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की अपेक्षा 579 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है। बाजार ऋणों और अल्प बचतों से क्रमशः 100 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये का अधिक संग्रह होगा। विशेष वाहक बांडों से चालू वर्ष में 875 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। जबकि बजट में 800 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने का अनुमान था। प्राप्तियों के अलावा, राज्य सरकारों से अर्थोपाय अभिमतों की वसूलियों में 200 करोड़ रुपये की और रुपया व्यापार करारों के अन्तर्गत तकनीकी ऋणों की वसूलियों में 117 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

32. जहां तक व्यय का संबंध है, आयोजना के लिए कुल बजटीय सहायता, बजट अनुमानों के 9,771 करोड़ रुपये से बढ़ कर, 10,394 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए, जिनमें आयोग विद्युत्-उत्पन्न निगम के कार्यक्रम भी शामिल हैं, दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में 156 करोड़ रुपये की वृद्धि की जा रही है। इसमें से अधिकांश वृद्धि का कारण यह है कि सूखे से प्रभावित राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक अभिमत आयोजना सहायता दी गई है।

33. केन्द्रीय आयोजना में, रेलों और कोयले के परिवहन में क्रमशः 157 करोड़ रुपये और 105 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं के सवितरणों की बढ़ती हुई मात्रा को देखते हुए, चालू वर्ष में उन्हें 389 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आयोजना सहायता दी जा रही है। डाक और तार विभाग के आंतरिक साधनों में हुई कमी को देखते हुए, अपेक्षाकृत अधिक अर्थात् 173 करोड़ रुपये को बजटीय सहायता की व्यवस्था की जा रही है। दूसरी ओर, कुछ अन्य सेक्टरों में आयोजना-व्यय में कमी होने का अनुमान है। कुल मिलाकर, संशोधित अनुमानों में केन्द्रीय आयोजना के लिए बजटीय सहायता में 467 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।

34. बजट अनुमानों में 15,100 करोड़ रुपये के आयोजना-भिन्न व्यय के लिये व्यवस्था की गई थी। कई कारणों से चालू वर्ष में यह व्यय भी अधिक होगा। रक्षा व्यय के लिये की गई व्यवस्था को 4,200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,600 करोड़ रुपये किया जा रहा है। इसी प्रकार, राज्य सरकारों को दिए जाने वाले आयोजना-भिन्न ऋणों की व्यवस्था को 1,296 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1,591 करोड़ रुपये किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण अल्प बचत संग्रहों में राज्यों का अधिक हिस्सा होना और अधिक अर्थोपाय अभिमतों का दिया जाना है, जो निस्सन्देह रूप से, इस वर्ष के दौरान ही वसूल किए जा रहे हैं। व्यापारियों के लिये दी जाने वाली आर्थिक सहायता (समिडी) को 650 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 700 करोड़ रुपये, कंट्रोल के कपड़े और हथकरघे से बने कपड़े पर पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 106 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 172 करोड़ रुपये और निर्यात के लिये नकद प्रतिपूरक सहायता (कैश कम्पेन्सेटरी सपोर्ट) और बाजार विकास के लिये की गई व्यवस्था को 390 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 477 करोड़ रुपये किया जा रहा है। रुपया व्यापार करारों के अन्तर्गत तकनीकी ऋणों के लिये की गई व्यवस्था को भी 50 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 175 करोड़ रुपये करना जरूरी है। संशोधित अनुमानों में, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की बढ़ी हुई पूंजी में भारत के हिस्से के प्रश्रवान के लिये 91 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन्हें और लेखाओं में हुए अन्य परिवर्तनों को हिसाब में लेने पर, संशोधित अनुमानों में आयोजना-भिन्न व्यय 16,160 करोड़ रुपये आंका गया है।

35. संशोधित अनुमानों में कुल व्यय 26,554 करोड़ रुपए का आंका गया है, जबकि इसकी तुलना में बजट में कुल 24,871 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान था। व्यय की तुलना में अब कुल 24,854 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है, जबकि बजट में 23,332 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान था। इस प्रकार चालू वर्ष में बजट अनुमानों के 1,539 करोड़ रुपए के घाटे की तुलना में 1,700 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है।

1982-83 के बजट अनुमान

36. वर्ष 1982-83 के बजट अनुमानों से पता चलेगा कि मैंने आयोजना परिषद को बढ़ाने की सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पिछले दो वर्षों में आर्थिक स्थिति में जो सुधार हुआ है, उसके हमें छठी आयोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दशा में जोरदार प्रयास करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं 1982-83 के बजट में केन्द्रीय आयोजना के लिये 11,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूँ। विभिन्न सेक्टरों के लिये धन-राशि नियत करने समय, मैंने 20-सूत्री कार्यक्रम में उल्लिखित, गरीबों को ऊँचा उठाने के कार्यक्रमों पर, और इसके अलावा बुनियादी ढाँचे से संबंधित सेक्टरों की पूंजी-निवेश सम्बन्धी आवश्यकताओं पर बल देने का प्रयत्न किया है।

37. अगले वर्ष का केन्द्रीय आयोजना परिषद 1981-82 के 8,619 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 27.6 प्रतिशत अधिक है। माननीय सदस्य निस्सन्देह रूप से यह महसूस करेंगे कि विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक व्यय को देखते हुए यह वृद्धि काफी अधिक है।

38. केन्द्रीय आयोजना का वित्तपोषण 7,343 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से और 3,657 करोड़ रुपए के आन्तरिक और बजट-बाह्य साधनों से किया जायेगा। इस प्रकार, आयोजना परिषद में सत्कारी क्षेत्र के उद्यमों के आन्तरिक और बजट-बाह्य साधनों का हिस्सा 33.2 प्रतिशत होगा, जबकि उस से पहले वर्ष 26.8 प्रतिशत था।

39. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का 1982-83 का कुल आयोजना-परिषद, जिसमें पश्चिम बंगाल का अनन्तिम परिषद भी शामिल है, 10,137 करोड़ रुपए आंका गया है। यह 1981-82 के 8,860 करोड़ रुपये के परिषद से 14.4 प्रतिशत अधिक है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता की राशि, 1981-82 के संशोधित अनुमानों की 3,462 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में, 4,002 करोड़ रुपए होगी। इस प्रकार, केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का 1982-83 का आयोजना परिषद कुल मिलाकर 21,137 करोड़ रुपए होगा, जो 1981-82 के 17,479 करोड़ रुपये के आयोजना-परिषद से 21 प्रतिशत अधिक है।

40. छठी आयोजना की नीति के अनुसार, अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण सेक्टरों के परिषद में काफी अधिक वृद्धि होने की परिकल्पना की गई है। कच्चे पेट्रोलियम के मामले में, चालू वर्ष में उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। उत्पादन में वृद्धि की गति को बरकरार रखने के लिये 1982-83 में तेल साफ करने के कारखानों और पेट्रो-रसायनों सहित, इस सेक्टर का परिषद 2,045 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो चालू वर्ष के परिषद से 90 प्रतिशत अधिक है। कोयले के परिषद को, 1981-82 के 578 करोड़ रुपये के परिषद से बढ़ा कर, 877 करोड़ रुपये किया जा रहा है, अर्थात् इसमें 52 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। विद्युत के क्षेत्र में, केन्द्रीय आयोजना का परिषद 929 करोड़ रुपये है, जबकि इसकी तुलना में 1981-82 में यह 721 करोड़ रुपये का था। कुल मिला कर, ऊर्जा सेक्टर का परिषद चालू वर्ष की अपेक्षा 62 प्रतिशत अधिक है और केन्द्रीय आयोजना-परिषद में इसका भाग 34 प्रतिशत है।

41. नई केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं में कोरबा और रामगुंडम सुपर तापीय विद्युत केन्द्रों में 1000-1000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन

क्षमता की स्थापना करने की परियोजनाएँ भी शामिल हैं। राज्यों और केन्द्र की आयोजनाओं में विद्युत सेक्टर का परिषद, कुल मिलाकर 3,977 करोड़ रुपये है, जबकि 1981-82 में 3,326 करोड़ रुपये का था। 1982-83 में 3500 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की जायेगी।

42. संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम में अनेक ऐसे क्षेत्रों में जोरदार प्रयास करने का आह्वान किया गया है जो अर्थ-व्यवस्था के लिये और हमारी जनता, विशेषतः समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये अति महत्वपूर्ण हैं। इस कार्यक्रम का कारगर ढंग से क्रियान्वयन करने से हम सामाजिक न्याय के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिये भी स्तरों पर सुमियोजित प्रयास करने की जरूरत है। उन कई क्षेत्रों के लिये, जिन पर 20-सूत्री कार्यक्रम जोर दिया गया है, 1982-83 में अधिक धन की व्यवस्था की गई है:

— केन्द्र और राज्यों की आयोजनाओं में सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास के लिये 2,133 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि 1981-82 में, 1,830 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी;

— केन्द्र और राज्यों की आयोजनाओं में कृषि के परिषद का, 1981-82 के 1,047 करोड़ रुपये के परिषद से बढ़ा कर 1,202 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें बालों, तिलहन, और बारानी खेती के लिये की गई व्यवस्था भी शामिल है;

— केन्द्रीय क्षेत्र में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिये 190 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि इसकी तुलना में 1981-82 में 145 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी अर्थात् इस में 31 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इतनी ही धन-राशि राज्यों द्वारा जुटाई जायेगी। प्रत्येक खण्ड का 8 लाख रुपये प्राप्त होंगे जब कि 1981-82 में 6 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। इस व्यवस्था से 1982-83 में 30 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को सहायता प्राप्त होने का अनुमान है;

— राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिये भी केन्द्रीय आयोजना में व्यवस्था को बढ़ा कर 190 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके लिये भी इतनी ही रकम की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जायेगी। समाज के लिए इस कार्यक्रम में टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण होने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 35 करोड़ कार्यविवर्षों का रोजगार पैदा होने की सम्भावना है;

— वर्ष 1981-82 के लिये अनुमानित जातियों के वास्ते विशेष संघटक आयोजनाओं के लिये 110 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई थी, उसे बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति विकास निगमों केन्द्र द्वारा 13.5 करोड़ की पूंजी लगाई जायेगी; इन निगमों में इतनी ही रकम का अंशदान राज्यों द्वारा किया जायेगा। 1982-83, में जनजाति उप-आयोजना में 95 करोड़ रुपए के परिषद की व्यवस्था की गई है, जो पहले से अधिक है;

— केन्द्र-प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के परिषद को बढ़ाकर 127.5 करोड़ रुपए किया जा रहा है ताकि राज्यों के 273 करोड़ रुपए के आयोजना परिषद की अनुपूर्ति की जा सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमानतः 45,000 समस्याग्रस्त गांवों को शामिल किया जायेगा।

— गांवों के भूमिहीन लोगों को भूकान बनाने के लिये स्थान देने के वास्ते 74 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और राज्यों की आयोजनाओं में गंदी बस्तियों के वातावरण में सुधार करने के लिये 29 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है;

— गांवों में बिजली लगाने के लिये 354 करोड़ रुपये के परिषद की योजना है। 1982-83 में 25,000 गांवों में बिजली पहुंचाई जायेगी और 4.25 लाख पम्प-सेटों को ढिंसी दी जायेगी;

— 75,000 बायोमैस संयंत्रों की स्थापना करने के काम में सहायता देने के लिये 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि 1981-82 में 35,000 संयंत्रों की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार, 1982-83 में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सामाजिक वनपालन योजना शुरू की जा रही है। इन वनरोपण कार्यक्रमों से, अत्यावश्यक ईंधन की लकड़ी मिलने के अलावा भूमि के काटव को रोकने और पारिस्थितिक सन्तुलन को फिर से कायम करने में सहायता मिलेगी;

—परिवार नियोजन परियोजना को बढ़ाकर 245 करोड़ रुपये आ रहा है, जबकि 1981-82 में यह राशि 155 करोड़ रुपये थी। इस बात की देखभाल हुए कि स्वास्थ्य गाइड परिवार नियोजन अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, केन्द्र ने ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना के लिये पूरी रकम की व्यवस्था करने का निश्चय किया है;

—स्वास्थ्य की देखभाल के लिये केन्द्रीय आयोजना में 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे स्वास्थ्य की प्राथमिक देखभाल की सामान्य सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि हो जायेगी और कुछ रोग, क्षय रोग और श्रमपन का नियंत्रण करने के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को तेज करने में सहायता मिलेगी। इन कार्यक्रमों में रोग का शीघ्र पता लगाने और उपचार पर जोर दिया जायेगा। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के प्रयोजन से राज्यों के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में 82 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है;

—केन्द्रीय आयोजना में महिलाओं के कल्याण के कार्यक्रम के लिये लगभग 16 करोड़ रुपये का परियोजना होगा। यह राशि राज्यों की आयोजनाओं में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त होगी। प्रौढ़ महिलाओं की कार्यात्मक साक्षरता के कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया जा रहा है जिसके लिये 4.6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है जबकि 1981-82 में इसके लिये 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी;

—एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम को चारों आयोजना के अंतर्गत 1000 परियोजनाओं में लागू किया जा रहा है, जबकि पहले लक्ष्य 600 परियोजनाओं का था। 1982-83 में 320 और परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है;

—प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिये 1982-83 में केन्द्रीय आयोजना में 14.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस व्यय का अधिकतर भाग ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना के लिये है। 1982-83 में 75 और जिलों में ऐसी परियोजनाएं शुरू किये जाने का प्रस्ताव है;

—केन्द्रीय आयोजना और राज्यों का आयोजनाओं में ग्राम और लघु उद्योगों के विकास के परियोजना को बढ़ा कर 340 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि 1981-82 में इस काम के लिये 315 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

43 पहाड़ी इलाकों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता की राशि बढ़ा कर 112 करोड़ रुपये कर दी गई है जबकि 1981-82 में यह राशि 92 करोड़ रुपये की थी। सरकार ने हाल में सहायता के उधार ऋणों की सभी पहाड़ी इलाकों पर लागू कर दिया है जिसके अनुसार 90 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है।

44 परिवहन सेक्टर के, जिसमें रेलवे सड़क, पत्तन और नागर विमानन शामिल हैं, केन्द्रीय आयोजना परियोजना को 1981-82 के 1,535 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1,757 करोड़ रुपये किया जा रहा है। मेरे सहयोगी रेल मंत्री ने सदन को पहले ही 1982-83 की रेलवे आयोजना के बारे में बता दिया है। पत्तनों पर भीड़-भाड़ को दूर करने के लिये आपूर्तिकीकरण का एक जोरदार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसमें पत्तनों पर कटेनरों के उद्घाटन-धरन को सुविधाओं को बढ़ाना और अतिरिक्त घाटों के निर्माण का काम शामिल है।

45 वर्ष 1982-83 के लिये आयोजना में भारी उद्योग विभाग और औद्योगिक विकास विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के लिये 480 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के लिये 97 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है। इसमें नागालैंड में तुली और आसाम में नौगांग और काछार में तीन बड़ी कागज परियोजनाओं के लिये 84 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी शामिल है। सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि नागालैंड कागज परियोजना में शीघ्र ही उत्पादन होने लगेगा। सरकारी क्षेत्र की तीन सीमेंट परियोजनाओं का काम 1982-83 में शुरू हो जायेगा। 1982-83 में देश में सीमेंट उत्पादन की स्थापित क्षमता 380 लाख मेट्रिक टन हो जाने की सम्भावना है जबकि 1981-82 में यह 320 लाख मेट्रिक टन थी।

46 वर्ष 1982-83 में इस्पात के लिये आयोजना परियोजना परियोजना 860 करोड़ रुपये का है, इस राशि में विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के लिये 250 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। 12 लाख मेट्रिक टन की क्षमता के पहले चरण के 1985 के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। विजय नगर इस्पात संयंत्र परियोजना के लिये कच्चे माल की हवाई के लिये परिवहन की व्यवस्था करने का काम चल रहा है। आयोजना में उड़ीसा एल्युमीनियम परियोजना के लिये 140 करोड़ रुपये का परियोजना भी शामिल है।

47 रसायनों और उर्वरकों के सेक्टर के लिये 507 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें थाल वैशेष परियोजना के लिये 210 करोड़ रुपये और हजोरा परियोजना के लिये 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी शामिल है।

48 1981 में उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण इस बात का प्रमाण है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमारे देश ने कितनी प्रभावशाली प्रगति की है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में भाग के रूप में जून, 1981 में एपल अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था। इसका उपयोग विभिन्न प्रयोगों जैसे राष्ट्रीय दूरदर्शन और रेडियो प्रसारण, ग्रंथीय (डिजिटल) संचार संगणकों के अनुसंधान और एस० टी० डी० के लिये किया जा रहा है। सरकार का एक मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। 1982-83 की केन्द्रीय आयोजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेक्टर के लिये 184 करोड़ रुपये के परियोजना की व्यवस्था की गई है।

49 सरकार ऊर्जा के नवीकरण योग्य साधनों को विशेष महत्व देती है। अतिरिक्त ऊर्जा साधन आयोग (कमीशन फार एक्सीशनल सोर्सेज आफ एनर्जी) ने सौर, तापीय, प्रकाश-बोलीय, वायु, जैव-पिंड (बायोमास) और एकीकृत ऊर्जा प्रणालियों के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास तथा प्रदर्शन परियोजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने सौर ऊर्जा सम्बन्धी उपकरणों के निर्माण को औद्योगिक लाइसेंसिंग से छूट दे दी है।

50 हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा दक्षिणी ध्रुव का अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाया, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिछले वर्ष हमारे जहाजों द्वारा समुद्र तल से बहु-धात्विक नदियों का पहली बार संग्रह किये जाने के बाद, हिन्द महासागर में विस्तृत सर्वेक्षण करने का काम हाथ में लेने का प्रस्ताव है। हाल में बनाये गये महासागर विकास विभाग के लिये, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सेक्टर की आयोजना में 17 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

51 हालांकि मैंने अगले वर्ष के आयोजना-भित्त व्यय को संश्लिष्ट रखने की कोशिश की है, फिर भी कुछ वृद्धियां अपरिहार्य हो गई हैं। रक्षा व्यय का अनुमान, चाबू वष के संशोधन अनुमानों के 4,600 करोड़ रुपये की तुलना में, 5,100 करोड़ रुपये का है। मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य मेरे साथ इस बात पर सहमत होंगे कि देश के बाह्य के अनिश्चित वातावरण को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की समय आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिये।

भाग ख

52. राज्यों की आयोजना-भिन्न ऋण देने के लिये, जिनमें अर्थोपाय ग्राम भी शामिल हैं, 1,732 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि 1981-82 में 1,591 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। आन्तरिक और विदेशी ऋणों में वृद्धि होने के कारण, जिनका उपयोग विकास कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था करने के लिये किया जाता है, व्याज के लिये व्यवस्था, जो 1981-82 के संशोधित अनुमानों में 3,200 करोड़ रुपये है, बढ़ कर 1982-83 में 3,800 करोड़ रुपये हो गई है। छावनीयों, उर्ध्वको और कंट्रोल के कपड़े तथा हथकरघे के कपड़े के लिये आर्थिक सहायता देने के लिये 1,270 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। निर्धन के लिये नकद प्रतिपूर्क सहायता और बाजार विकास सहायता देने के लिये 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

53. मैं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें और पेंशन-राहत देने के लिये 1982-83 में 350 करोड़ रुपये की एक-मुश्त व्यवस्था भी कर रहा हूँ। सरकार को पेंशनभोगियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए उन्हें कुछ राहत दी जानी चाहिए। पिछले वर्ष के बजट में मेरे पूर्ववर्ती सुप्रतिष्ठित वित्त मंत्री ने पेंशनभोगियों के लिये कुछ राहतों की घोषणा की थी। मैं विशेष रूप से पेंशन के निम्नलिखित स्तर पर अब कुछ और राहत देने का प्रस्ताव करता हूँ। राहत सहित, पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ा कर 150 रुपये मासिक कर दी जायेगी। राहत सहित, पारिवारिक पेंशन की राशि भी बढ़ा कर 140 रुपये मासिक कर दी जायेगी। इन उपायों से कम पेंशन पाने वाले लगभग 7 लाख पेंशनभोगियों, और पारिवारिक पेंशन पाने वाले 2 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। मैं यह भी बताता चाहूँगा कि पूर्वोक्त श्रेणी के लगभग 85 प्रतिशत व्यक्ति भूतपूर्व रक्षा कर्मचारी हैं। सबन मेरे साथ इस बात पर सहमत होगा कि जिन लोगों ने अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्ष देश की रक्षा में लगाये हों, वे ऐसी हर सहायता पाने के पात्र हैं, जो हम उन्हें प्रदान कर सकते हैं।

54. वर्ष 1982-83 का कुल आयोजना-भिन्न व्यय 17,874 करोड़ रुपये आंका गया है, जबकि इसकी तुलना में 1981-82 के संशोधित अनुमान 16,160 करोड़ रुपये के हैं।

55. जहाँ तक 1982-83 में होने वाली प्राप्तियों का सम्बन्ध है, कराधान की मौजूदा दरों पर सकल कर राजस्व 17,614 करोड़ रुपये आंका गया है, जबकि 1981-82 के संशोधित अनुमान 15,754 करोड़ रुपये के हैं। 1982-83 में करों में राज्यों के हिस्से का अनुमान 4,716 करोड़ रुपये लगाया गया है, जबकि चालू वर्ष में 4,274 करोड़ रुपये का अनुमान है। इस प्रकार केन्द्र का निवल कर राजस्व, चालू वर्ष के 11,480 करोड़ रुपये की तुलना में, 12,898 करोड़ रुपये होगा।

56. बाजार ऋणों से 3,200 करोड़ रुपये की प्राप्तियाँ होने का अनुमान है, जबकि 1981-82 में 2,900 करोड़ रुपये की प्राप्तियाँ हुई थीं। अल्प बचतों से, 1981-82 के संशोधित अनुमानों के 1,500 करोड़ रुपये की तुलना में, 1,400 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। ऋण-परिशोधन की रकम का घटने के बाद, 1,669 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि 1981-82 में 1,381 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त हुई थी।

57. इन प्राप्तियों को और कर-भिन्न राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों में होने वाली अन्य वृद्धियों तथा रेलों के किराये और घाटों की दरों और डाक और तार की दरों में हुए परिवर्तनों के प्रभावों को हिसाब में लाने के बाद, जिनका उल्लेख मैं कुछ देर बाद में करूँगा, 1982-83 में कुल 27,134 करोड़ रुपये की प्राप्तियाँ होने का अनुमान है। व्यय का अनुमान 29,219 करोड़ रुपये लगाया गया है। इस प्रकार, कराधान की मौजूदा दरों पर बजट का कुल घाटा 2,085 करोड़ रुपये का होगा।

58. महोदय, कर प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में पहले, मैं उन गुरु उद्देश्यों का उल्लेख करना चाहूँगा जिन्हें मैंने ध्यान में रखा है। यद्यपि हम इस बात में सैन की साम ले सकते हैं कि मुद्रास्फीति को कम करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन यह बात अधिक महत्वपूर्ण है कि बजट से मुद्रास्फीति के बढ़ने की सम्भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। वियेकपूर्ण सीमाओं में अधिक के पूरे न किए गए किसी घाटे में मुद्रास्फीति अन्तर्निहित होती है। इससे कीमतों की प्रवृत्ति के बारे में आश्चर्य भी पैदा होनी है। अतः मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि जहाँ तक व्यवहार्य हो, बजट के घाटे को कम से कम रखा जाए।

59. मेरा दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि ऐसे उपायों से बचा जाए जिनका कम आमदनी वाले और मध्यम आमदनी वाले लोगों पर अनुचित बोझ पड़ता हो। मुद्रास्फीति के समय में इन लोगों पर सब से बुरा असर पड़ता है।

60. जैसा कि मैंने पहले ही संकेत दिया है, इस बजट का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन और बचतों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिए जाएँ। बचतों के अधिक होने और उत्पादकता में वृद्धि होने से मुद्रास्फीतिकारी बचावों को कम करने में सहायता मिल सकती है और साथ ही इससे विकास के लिए साधनों का निर्माण भी हो सकता है। वर्ष 1981-82 में सुदृढ़ कृषि एवं औद्योगिक वृद्धि के वातावरण में राजस्वों में तेजी से वृद्धि और मुद्रास्फीति की दर में कमी से इस कारणा की पुष्टि होती है।

61. महोदय अब मैं प्रत्यक्ष करों की ओर आता हूँ। मेरा पहला प्रस्ताव बेतनभोगी करदाताओं के बारे में है। ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें यह कहा गया है कि रहन सहन की लागत में वृद्धि को देखते हुए आयकर से छूट की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। मैं, सिद्धांत रूप से, यह स्वीकार नहीं करता कि कर से छूट की सीमाएं रहनसहन के खर्च के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए। लेकिन साथ ही मैं यह विश्वास करता हूँ कि न्यूनतम कर योग्य आय खण्ड के बेतनभोगी करदाताओं को कुछ राहत दी जानी चाहिए। इस समय, बेतनभोगी करदाता बेतन के 20 प्रतिशत लेकिन अधिक से अधिक 5,000 रुपये की सीमा तक मानक कटौती के हकदार हैं। मैं कटौती की दर को, 5,000 रुपये की अधिकतम सीमा को छोड़े बिना, 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस से 20,000 रुपये तक के बेतन भोगियों को काफी राहत मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप 1982-83 में 21.58 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी।

62. राहत के दूसरे उपाय का सम्बन्ध उचित रूप से, उन लोगों के लिए है जो अपना कार्यशील जीवन समाप्त कर सेवा से निवृत्ति होते हैं। मैं, कुछ बातों के अधीन, रिटायर होने वाले कर्मचारियों को, उपयोग न की गई अर्जित छुट्टी के बदले नकद भुगतान के लिए आयकर से छूट का प्रस्ताव करता हूँ।

63. ऐसे करदाता जिन्हें मकान किराया भत्ता नहीं मिलता उनके द्वारा प्रदा किए गए मकान किराए के लिए 300 रुपये प्रति मास के हिसाब से कटौती के हकदार होते हैं। लेकिन, मकान किराया भत्ता देने वाले कर्मचारी, उनके द्वारा प्राप्त किए गए किराए के सम्बन्ध में 400 रुपये प्रति मास के हिसाब से छूट के हकदार होते हैं। मैं, उन कर्मचारियों के मामले में जिन्हें मकान किराया भत्ता नहीं मिलता, छूट की अधिकतम सीमा को 300 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

64. अपने मकान में स्वयं रहने वाला मकान मालिक, मकान के वार्षिक किराया मूल्य में से, वार्षिक किराया मूल्य के आधे के बराबर या 1,800 रुपये की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती का हकदार होता है। मैं इस सीमा को 1,800 रुपये से बढ़ाकर, 3,600 रुपये कर देने का प्रस्ताव करता हूँ।

65. कर के प्रयोजन में, किसी नए बनाव, गण, मकान के, किराए पर उठाए जाने की स्थिति में, वार्षिक किराया मूल्य में प्रत्येक रिहायणी यूनिट के मामले में 5 वर्ष की अवधि के लिए 2,400 रुपए की कटौती की जाती है। मकानों के निर्माण की बढ़ावा देने के उद्देश्य से, विशेषकर कम आय वाले लोगों का प्रोत्साहन देने के लिए, मैं इस सीमा को 2,400 रुपए से बढ़ाकर 3,600 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

66. मैं जीवन बीमा, भविष्य निधि के अंशदानों आदि जैसी दीर्घ-वधिक बचतों के सम्बन्ध में कटौती की योजना को उदार बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। पहले 6,000 रुपए की अधिक बचतों के लिए 100 प्रतिशत और अगले 6,000 रुपए की ऐसी बचतों पर 50 प्रतिशत और शेष बचतों पर 40 प्रतिशत के हिसाब से कटौती दी जाएगी। कटौती के लिए अधिक बचतों की सीमा को भी 30,000 रुपए से बढ़ा कर 40,000 रुपए किया जा रहा है। लेखकों, नाटककारों, कलाकारों संगीतज्ञों, अभिनेताओं, खिलाड़ियों और एथलीटों के मामले में इस सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ा कर 60,000 रुपए किया जा रहा है। इन दीर्घवधिक बचतों से पूरे वर्ष में राजस्व की 26.17 करोड़ रुपए की और 1982-83 में 19.76 करोड़ रुपए की हानि होगी। कुछ समय बाद, कर्जाताओं के लिए बचतों के पात्र माध्यमों की बड़े पैमाने पर व्यवस्था करना बांछनीय होगा। अतः मैं केन्द्रीय सरकार की अधिसूचित प्रतिभूतियों में निवेश के सम्बन्ध में मौजूबा कर-रियायतों के लिए जाने का प्रस्ताव करता हूँ।

67. मुझे पता चला है कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी की गई नई जीवन बीमा पालिसियों में से लगभग 15 प्रतिशत पालिसियां अगले वर्ष के समाप्त होने से पहले ही व्यपगत हो जाती हैं। पालिसियां जारी होने के इतनी जल्दी बाक, इतनी अधिक संख्या में उनका व्यपगत हो जाना बिम्बा का विषय है। इसका अर्थ यह भी है कि वह उद्देश्य, जिसके लिए ऐसी पालिसियों के प्रीमियमों पर करों से रियायत दी जाती है और जिसका मनोरथ दीर्घवधिक बचतों को बढ़ावा देना है, निष्फल हो जाता है। अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि ऐसे मामलों में जहां कोई करदाता दो वर्षों के प्रीमियम भ्रवा करने से पहले पालिसी समाप्त कर देता है, वहां यदि पालिसी के अन्तर्गत कोई प्रीमियम भ्रवा भी किए गए हों, उनके सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं दी जाएगी और यदि कोई कटौती दे दी गई हो, तो वह वापस ले ली जाएगी।

68. बचतों और निवेशों को बढ़ावा देने के मौजूबा प्रोत्साहनों के अधीन सरकारी प्रतिभूतियों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों, बैंक जमा और भारतीय कंपनियों के शेयरों जैसी विनिविष्ट परिसम्पत्तियों में निवेश से होने वाली 3,000 रुपए तक की आमदनी पर आयकर से छूट दी जाती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों से प्राप्त 2,000 रुपए की आमदनी पर भी कर से छूट प्राप्त है। मैं 3,000 रुपए की अधिकतम सीमा को 4,000 रुपए तक बढ़ाने और यूनिटों से प्राप्त होने वाली आमदनी की अधिकतम सीमा को अलग से 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस उपाय से पूरे वर्ष में 12.12 करोड़ रुपए की और 1982-83 में 9.09 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

69. मैं, एक समानांतर उपाय के रूप में, विनिविष्ट विस्तीय परि सम्पत्तियों में निवेश के मूल्य की अधिकतम सीमा को, धन कर से छूट के प्रयोजन से, 1,50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,65,000 रुपए कर देने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों के सम्बन्ध में अलग से दी गई 25,000 रुपए की छूट को 35,000 रुपए तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। पूरे वर्ष में, इस उपाय से 1.54 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी लेकिन 1982-83 में कोई हानि नहीं होगी।

70. इस समय करदाताओं को, उनकी कर-योग्य आय का हिसाब लगाते समय, उनके द्वारा नई औद्योगिक कंपनियों और ऐसी कंपनियों के

इक्विटी शेयरों में किए गए निवेशों के 50 प्रतिशत तक की कटौती दी जाती है जो रिहायणी मकानों के निर्माण और खरीद के लिए दीर्घवधिक विन की व्यवस्था करती हो। किसी एक वर्ष में इस कटौती की गतान निवेश की अधिकतम अधिक सीमा 10,000 रुपए तक सीमित है। ऐसी कंपनियों में अधिकाधिक निवेश के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मैं निवेश की इस सीमा को बढ़ा कर 20,000 रुपए कर देने का प्रस्ताव करता हूँ।

71. यद्यपि मैंने कर-योग्य निम्नतम आय वर्गों को कुछ शर्तों दी हैं, लेकिन मेरे विचार से ऊंची आय के वर्गों पर लगने वाले कर दी दगों को बढ़ाने की गुंजाइश है। अतः मैं व्यक्तिगत कराधान की वर्गों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ जिससे 60,001 रुपए से 70,000 रुपए तक के खण्ड पर आयकर की दर को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 52.5 प्रतिशत और 85,001 रुपए से 1,00,000 रुपए तक के खण्ड पर आयकर की दर को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 57.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस उपाय से पूरे वर्ष में 3.24 करोड़ रुपए और 1982-83 में 2.43 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

72. लाभार्थों, प्रतिभूतियों पर व्याज और अन्य व्याज की रकमों के स्त्रोत पर काट लिए जाने के कारण बहुत से छोटे-छोटे निवेशकर्ताओं को, जिनकी कर-योग्य आय छूट की सीमा से कम होती है, बड़ी परेशानी और तकलीफ होती है। ऐसे व्यक्तियों की सुविधा के लिए, मैं ऐसी व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव करता हूँ कि आयकर की राशि स्त्रोत पर नहीं काटी जाएगी यदि प्राप्तकर्ता ऐसी आय के बाना को इस आशय का घोषणापत्र प्रस्तुत कर दे कि सम्बद्ध वर्ष में लिए उसकी अनुमानित आय छूट की सीमा से कम होगी।

73. मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचित केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की ऐसी प्रतिभूतियों पर अदा किए गए व्याज में से स्त्रोत पर पर की रकम नहीं काटी जाएगी।

74. विदेशों में आय अर्जित करने वाले उन भारतीय नागरिकों को जो थोड़े समय के लिए भारत आते हैं, कराधान के प्रयोजन से भारत में "निवास" के लिए निर्धारित की गई कसौटियों से बड़ी तकलीफ होती है। किसी व्यक्ति को किसी वर्ष भारत का निवासी तब माना जाता है जब वह उस वर्ष में यहाँ केवल 30 दिन के लिए ठहरा हो और उसका 182 दिन या अधिक समय के लिए यहाँ निवास-स्थान हो। चूंकि इस कसौटी से भारत से बाहर काम करने वाले उन व्यक्तियों को तकलीफ होती है, जो अपेक्षाकृत थोड़े समय के लिए भारत की यात्रा पर आते हैं, इस लिए मैं निवास की इस कसौटी को हटाने का प्रस्ताव करता हूँ।

75. एक और कसौटी के अधीन सम्बद्ध वर्ष से पहले के बार वर्षों में 365 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहने वाला व्यक्ति उस वर्ष 60 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहकर उस वर्ष के लिए भारत का निवासी बन पाता है। विदेशों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के मामले में, जो भारत में छुट्टी पर या भ्रमण के लिए आते हैं, यह अवधि 90 दिन है, मैं यह लाभ स्वनियोजित और अन्य धर्मों में लगे व्यक्तियों को भी देने का प्रस्ताव करता हूँ चाले विदेशों में उनकी आजीविका या भारत में उनकी यात्रा का उद्देश्य कुछ भी हो।

76. रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों की विदेशों में प्राप्त आय पर अब कर लगता है याव वे उस वर्ष 60 दिन से अधिक समय के लिए भारत में रहे हों। मैं इस व्यवस्था को उदार बनाना चाहता हूँ, ताकि किसी भी भारतीय नागरिक को जो किसी वर्ष रोजगार के लिए भारत से बाहर गया हो, तब तक निवासी नहीं माना जाएगा, जब तक वह उस वर्ष भारत में 182 दिन या इससे अधिक समय के लिए भारत में न रहा हो।

77. श्रैव मैं विदेशी मुद्रा की आमदनी के बारे में कुछ प्रस्तावों को लेता हूँ। मैं उन नियमनों को, जिनके किसी भी वर्ष के निर्यात का मूल्य, उस वर्ष के ठीक पहले के वर्ष के निर्यात-मूल्य से 10 प्रतिशत में अधिक हो, कर संबंधी कुछ राहतें देने का प्रस्ताव करता हूँ। कर सम्बन्धी यह राहत, जिसका हिस्सा प्रतिरिक्त निर्यात-मूल्य के विनिर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार लगाया जाएगा, निर्यात लाभ पर अन्यथा वेध आयकर के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाणी जिसमें वह दर बताई जाएगी जिस पर कर सम्बन्धी यह राहत दी जाएगी और इस रियायत के प्रयोजन के लिए अर्हक मास का ब्यौरा दिया जाएगा।

78. हमारे प्रति बताने वाले हमारे ठेकेदारों की प्रतियोगितात्मक क्षमता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, जिन्होंने भारत के बाहर परियोजनाओं के काम हाथ में ले रखे हैं, उनके द्वारा ऐसे विदेशी ठेकों से कमाए गए लाभ की 25 प्रतिशत राशि की, कुछ शर्तों के अधीन, मैं छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

79. विदेशों में बैंक कारबार करने वाले भारतीय बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत बनाने के उद्देश्य से, मैं उन बैंकों को, जिन्हें इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त है, विशेष प्रारक्षित निधि खाते में ले जाई गई अपनी आय में 40 प्रतिशत तक की कटौती देने का प्रस्ताव करता हूँ।

80. ध्याज-कर अधिनियम के अन्तर्गत लगाया गया ध्याज-कर हमारी श्रृण संबंधी नीति का अभिन्न अंग है। लेकिन, औद्योगिक परियोजनाओं की शगत में घुड़ हो जाने को ध्यान में रखते हुए मैं अनुसूचित बैंकों को, उनके द्वारा पूंजीगत संयंत्रों और मशीनरी के आयात के लिए किए गए श्रृणों पर प्राप्त ध्याज पर, ध्याज-कर को धरायनी में छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। पूंजीगत संयंत्र और मशीनरी के निर्यात की प्रतियोगितात्मक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से, मैं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारत से बाहर पूंजीगत संयंत्रों और मशीनरी के निर्यात के लिए धास्थित धरायनी के आधार पर किए गए श्रृण पर धदा किए गए ध्याज की राशि पर कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

81. सरकारी प्रयोगशालाओं, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों, मान्यता-प्राप्त संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में विकसित औद्योगिकी से वस्तुओं के निर्माण के लिए स्थापित मशीनों और संयंत्रों के संबंध में 35 प्रतिशत की ऊंची दर से निवेश, छूट (इनवेस्टमेंट ग्राउंट्स) दी जाती है। यह रियायत 31 मार्च, 1982 तक स्थापित मशीनों और संयंत्रों के बारे में उपलब्ध है। मैं इस कर-रियायत को पांच वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

82. किसी देशी कंपनी को किसी ऐसी भारतीय कंपनी से, जो अनन्य रूप से अथवा लगभग अनन्य रूप से विनिर्दिष्ट वस्तुओं का निर्माण करती हो, प्राप्त लाभों को आयकर से पूर्णतया छूट प्राप्त है। मैं आधारभूत औषधों, संश्लिष्ट रबड़ और रबड़ रसायनों (जिनमें कार्बन ब्लैक भी शामिल है) के महत्व को देखते हुए, इन वस्तुओं का निर्माण करने वाली कंपनियों से भी प्राप्त लाभों को इस कर-रियायत का लाभ देने का प्रस्ताव करता हूँ।

83. इस समय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनी ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए अधिमों से सम्बन्धित प्रशोध्य और संविद्य श्रृणों के लिए की गई व्यवस्था के बारे में इन बैंकों को कटौती करने की छूट दी जाती है। यह कटौती ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए कुल प्रोसत अधिमों के 1.5 प्रतिशत तक सीमित होगी है। ग्रामीण बैंकिंग को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सहायता देने के लिए, मैं इस कर-रियायत का लाभ इन बैंकों को भी देने का प्रस्ताव करता हूँ।

1388 GI/81--2

84. ऊर्जा में वृद्धि और पर्यावरण का संरक्षण उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। इसलिए मैं ऊर्जा की वृद्धि करने या पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रण करने अथवा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले उपकरणों और सिस्टमों के बारे में 30 प्रतिशत की दर से मूल्यहास की छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। अर्हक मदों की सूची यथामय अधिसूचन कर दी जाएगी।

85. इस समय, ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही अनुमोदित संस्थाओं को दिए गए दान के सम्बन्ध में करदाताओं को 100 प्रतिशत की कटौती की छूट प्राप्त है। मैं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली अनुमोदित संस्थाओं को दिए जाने वाले दान के सम्बन्ध में भी यह रियायत देने का प्रस्ताव करता हूँ।

86. माननीय सदस्यों का यह सुन कर खुशी होगी कि मैं राष्ट्रीय वान निधि को दिए जाने वाले दान को राष्ट्रीय महत्व की अन्य निधियों जैसे राष्ट्रीय रक्षा निधि, जवाहर लाल नेहरू स्मारक निधि और प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि को दिए जाने वाले दान के समकक्ष रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

87. मेरा विचार है कि पूंजीगत लाभ के सम्बन्ध में कराधान को कुछ युक्तिसंगत बनाया जाना वांछनीय है। गैर-निगमित करदाताओं के मामले में 5,000 रुपए तक के दीर्घाधिक पूंजीगत लाभों की पूर्णतया कटौती की जाती है। शेष राशि के 25 प्रतिशत की कटौती की अनुमति दी जाती है। यदि लाभ का सम्बन्ध भूमि और इमारतों से हो; और यदि लाभ का सम्बन्ध अन्य परिसम्पत्तियों से हो तो शेष राशि के 40 प्रतिशत की कटौती की अनुमति दी जाती है। मेरा इन उपबन्धों में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि कटौती को उस अवधि से जोड़ दिया जाए, जिस अवधि तक करदाता द्वारा पूंजीगत परिसम्पत्ति रखी गई हो, और उन मामलों में अपेक्षाकृत अधिक कटौती की अनुमति दी जाए, जिनमें परिसम्पत्ति अधिक लम्बी अवधि के लिए रखी गई हो। लेकिन सोने, बुलियन अथवा आभूषणों से सम्बन्धित पूंजीगत लाभों के सम्बन्ध में कुल कटौती 50,000 रुपए तक ही सीमित रखी जाएगी।

88. मकानों की भोषण कमी है और मकान-निर्माण के क्रियाकलापों को गति प्रदान की जानी जरूरी है। उन करदाताओं को प्रोत्साहन देने के लिए, जिनके पास अपना रिहायशी मकान नहीं है, मैं अन्य परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत से उद्भूत दीर्घाधिक पूंजीगत लाभों को उन मामलों में कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ, जिनमें करदाता द्वारा निवल लाभ का निवेश किसी रिहायशी मकान में कर दिया जाए।

89. इस समय, किसी मकान के अन्तर्गत से प्राप्त पूंजीगत लाभ को उस हद तक आयकर से छूट प्राप्त होती है, जिस हद तक उसका इस्तेमाल करदाता द्वारा एक विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर निजी रिहायश के प्रयोजन से मकान के निर्माण अथवा उस की खरीद के लिए किया जाए। इन शर्तों के कारण प्रायः कठिनाइयां होती हैं। इसलिए मैं इन प्रतिबन्धात्मक शर्तों को हटाने का प्रस्ताव करता हूँ।

90. पूर्त और धार्मिक न्यासों के लिए यह जरूरी है कि वे आयकर अधिनियम में निर्धारित निवेश-शर्तों के अनुसार निवेश करें। जिस न्यास ने अपने निवेश में इस शर्त के अनुसार परिवर्तन नहीं किया, उसे 1982-83 के कर-निर्धारण वर्ष से कर में छूट नहीं मिलेगी। इन न्यासों को अपने न्यास के स्वरूप में परिवर्तन करने की पर्याप्त सूचना दे दी गई थी और सामान्यतः मैं इन उपबन्धों में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव न करता। लेकिन, मैंने देखा है कि पूर्त और धार्मिक न्यासों से सम्बन्धित समूचे उपबन्धों पर अधिक प्रशामन मुद्धार आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। चूंकि सरकार इस मामले में आयोग की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहेगी, इसलिए मैं सम्बन्धित उपबन्धों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ, ताकि इन न्यासों को 1982-83 के कर-निर्धारण वर्ष से आयकर से छूट मिलती श्रव न हो जाए।

91. मेरे सुप्रसिद्धिपूर्वक विस्तार में 31 मार्च, 1981 को लोक सभा में घोषणा की थी कि आयकर के उन उपवर्गों को, जिनका सम्बन्ध व्यापक निधियों के निवेश-रहित से है, संशोधित किया जाएगा, ताकि पूर्ण और धार्मिक न्यायों अथवा संस्थाओं को व्यापक-निधियों को प्रचलन सम्पत्ति में भी निवेश करने की अनुमति दी जा सके। मैं उनके द्वारा दिए गए आग्रहों को पूरा करने के लिए आयकर अधिनियम के मंगल उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

92. यद्यपि वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1980 के द्वारा कृषि सम्पत्ति पर धन कर लगाया जाना बन्द कर दिया गया था, लेकिन चाय, काफी, रबड़ और इलायची बागानों के मालिकों पर धन कर लगाया जाता रहा। हमारा अनुभव यह है कि उन कृषि भूमियों को, जो ऐसे बागानों का भाग हों, मूल्यांकन करने में प्रशासनिक कठिनाइयाँ, तंग किए जाने की शिकायतें और मुकदमेबाजी उत्पन्न हो जाती है। इस कर से होने वाली प्राप्ति भी बिल्कुल गण्य होती है। इसलिए, मैं ऐसे बागानों पर भी धन कर लगाना बन्द करने का प्रस्ताव करता हूँ।

93. किसी करवाला के लिए अपने व्यवसाय या भाजीविका को चलाने के लिए आवश्यक औजारों और उपकरणों के मूल्य को, कुल मिलाकर 20,000 रुपये की राशि तक, धन कर से छूट प्राप्त है, जो अप्रयोजित प्रतीत होती है। मेरा इस राशि को 50,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। मैं धन कर से छूट के प्रयोजन से वाहनों के, जिनमें मोटर कारें भी शामिल हैं, मूल्य की वर्तमान 30,000 रुपये की उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

94. किसी सम्पत्ति के दान से सम्बन्धित लिखत पर दिए गए स्टाम्प शुल्क को, उन मामलों में जिनमें करदाता द्वारा दिए जाने वाले दान-कर की राशि 1,000 रुपये से अधिक हो, दान-कर से कटौती करने की छूट दी जाती है। मैं इस कटौती का लाभ उन मामलों में भी देने का प्रस्ताव करता हूँ, जहाँ देय दान-कर की राशि 1,000 रुपये से अधिक न हो।

95. होटल प्रामदनी कर अधिनियम, 1980 में लकड़ी होटलों की सकल आमदनी पर कर लगाए जाने का उपबन्ध है। चूँकि इस कर के लगाए जाने से भारत में विदेशी पर्यटकों के आने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए मैं इन होटलों को 27 फरवरी, 1982 के बाद प्रोद्भूत या उद्भूत अथवा उन्हें प्राप्त होने वाली प्रभाय आमदनी के सम्बन्ध में इस कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे राजस्व में लगभग 6 करोड़ रुपये की कमी होगी।

96. प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में अन्य प्रस्ताव अपेक्षाकृत कम महत्व के हैं। इसलिए, मैं यहाँ उनका उल्लेख करके सदन का समय नहीं लेना चाहूँगा।

97. माननीय सदस्यों ने यह नोट किया होगा कि मैंने प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखे हैं, उनमें मैंने बचत को काफी प्रोत्साहन देने के साथ-साथ कर प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया है। मैंने पूंजीगत लाभ कर को भी युक्तिसंगत बनाया है और जहाँ आवश्यक था, वहाँ कुछ रियायतें प्रदान की हैं।

98. अध्यक्ष महोदय, अब मैं अप्रत्यक्ष करों की ओर आता हूँ। पहले मैं सीमाशुल्कों को लेता हूँ। मेरा मुख्य प्रस्ताव सहायक सीमाशुल्कों के बारे में है। इस शुल्क को, जो 1973 के बजट से वार्षिक आधार पर लगाया जाता है, 1982-83 में जारी रखने का प्रस्ताव है। पिछले कुछ समय से भुगतान शेष की स्थिति पर तबाव बना हुआ है और आने वाले कुछ समय तक यह तबाव बना रहेगा। लेकिन उदार आयात प्रणाली हमारी आर्थिक नीतियों का घंग रहा है। इसे जारी रखा जाएगा ताकि विशेष रूप से अत्यावश्यक और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में निवेश और उत्पादन के मार्ग में बाधा न आए और उनकी गति धीमी न हो। लेकिन जो लोग इस कठिन समय में आयात कर सकते हैं, उन्हें उसके लिए कुछ अधिक प्रभावशील करने में सहायता देने का कोई ठोस कारण नहीं है। तदनुसार, मैं सभी

श्रेणियों के आयात पर, कुछ अपवादों के साथ, सहायक शुल्कों में 5 प्रतिशतता वस्तुओं की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ।

99. मैं सहायक शुल्कों में प्रस्तावित वृद्धि के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं जैसे कच्चे पेट्रोलियम, थोक पेट्रोलियम उत्पादों, जैसे मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल तेल, और कुछ अन्य वस्तुओं को, जिन पर सीमाशुल्कों की दरों में हाल में मुख्य समता के प्रयोजन से समायोजन किए गए थे, शामिल नहीं कर रहा हूँ। इन प्रस्तावों का पूरा व्यौरा बजट-पत्रों में उपलब्ध है।

100. सहायक सीमाशुल्कों से सम्बन्धित मेरे प्रस्तावों में 290 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

101. बाजार की मौजूदा स्थिति और कुछ चुने हुए उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को देखते हुए, बुनियादी सीमाशुल्कों में कुछ परिवर्तन करते जरूरी हैं। मैं बुनियादी सीमाशुल्कों की मूल्यानुसार दरों को कार्क और कार्क से बनी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 60 प्रतिशत करने, कुछ रंजक पदार्थों पर 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने तथा रंजक पदार्थों, वर्णकों तथा रंगों और पेंट तथा वानिशी पर 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं लोहे और इस्पात की कतिपय मदों जैसे स्टेनलेस इस्पात के मैल्डिंग स्क्रैप और तापरोधी इस्पात और कुछ किस्मों के मिश्रित इस्पात, जिनमें स्टेनलेस इस्पात और तापरोधी इस्पात शामिल नहीं हैं, पर भी बुनियादी सीमाशुल्कों की मौजूदा दरों को बढ़ाकर 60 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ। तंबाकी पाइपों और ट्यूबों, विनिर्दिष्ट विधिष्ठियों वाली ब्लैक और खोखली छड़ों पर लगने वाले बुनियादी सीमाशुल्क की प्रभावी दर को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जाएगा। पालिग्रेटर चिप्स पर बुनियादी सीमाशुल्क को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 140 प्रतिशत किया जा रहा है। इन प्रस्तावों से 42 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है।

102. यह याद दिला दिया जाए कि पिछले बजट में आयोजित अखबारी कागज पर, जिस पर अब भी भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है, 15 प्रतिशत मूल्यानुसार की प्रभावी दर से सीमाशुल्क लगाया गया था। सरकार को इस शुल्क के खिलाफ अप्पेलेटन प्राप्त हुए हैं। मैं इस मूल्यानुसार शुल्क को कुल 82.5 रुपये प्रति मेट्रिक टन के मात्रानुसार शुल्क में बदलने का प्रस्ताव करता हूँ, ताकि बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के पालस्वरूप इस शुल्क के भार में स्वतः वृद्धि न हो। इससे राजस्व में कोई कमी नहीं होगी।

103. देश के जस्ता और सीसा उद्योगों को निवेश्य वस्तुओं, विशेषतः आयोजित मान्द्रणों (काल्सेट्रेट्स) की कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस उद्देश्य से कि ये उद्योग अपनी क्षमता का अधिक उपयोग कर सकें, मैं आयोजित जस्ता मान्द्रणों पर लगने वाले सीमाशुल्क के कुल भार को 50 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत और सीसे के मान्द्रणों पर सीमाशुल्क के कुल भार को 50 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके साथ-साथ, मैं आयोजित जस्ता धातु पर मूल्यानुसार सीमाशुल्क को 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। राजस्व में होने वाली हानि को अंशतः प्रतिसंतुलित करने के लिए, मैं देश में उत्पादित जस्ता धातु, जस्ते के स्क्रैप और जस्ता उत्पादों पर उत्पाद-शुल्कों की दर में 715 रुपये प्रति मेट्रिक टन और सीसे की धातु और स्क्रैप पर सीमाशुल्क की दर में 371 रुपये प्रति मेट्रिक टन की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। जस्ते की पाइपों और ट्यूबों के उत्पाद शुल्क की मूल्यानुसार दर को 38.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 49.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, कुल मिलाकर, लगभग 11 लाख रुपये की हानि होगी।

104. नियमित बाजार में घटती हुई कीमतों के स्वर्ध में, भारतीय क्रोमाइट ग्रुप की प्रतियोगिता क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, मेरा क्रोमाइट के विभिन्न प्रेक्षों के ग्रुप और सामग्रियों पर लगने वाले

निर्यात शुल्क की मौजूदा मात्रानुसार दरों के स्थान पर 10 प्रतिशत का मूल्यानुसार शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इससे राजस्व में 1 करोड़ रुपए की कमी होगी।

105. मैं दो उधरकों -- केमियम प्रमोनियम नाइट्रेट और प्रमोनियम सल्फेट को सीमा शुल्कों से पूर्णतया छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। विद्युत-चालित टिलरों के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इंजनों और इन इंजनों के गैर-अन्तर्वेशन (नान-इंटर-वेंजेबल) हिस्सों पर लगने वाले आयात शुल्क को भी 125 प्रतिशत से घटा कर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

106. मैं जीवन रक्षक औषधों और दवाओं के उत्पादन के लिए आयात की जाने वाली 10 और थोक औषधों का पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। व्यापक अधिसूचित किया जा रहा है।

107. पिछले कुछ वर्षों में, सरकार राजस्व तंत्र का उपयोग इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास में नैजी लाने के लिए करती रही है। इस दिशा में एक और कदम के रूप में, मैं संगणकों, परिकलन यंत्रों, लेखापालन मशीनों, कैश रजिस्ट्रों और कतिपय इलेक्ट्रानिक उप-असेम्बलियाँ जैसी इलेक्ट्रानिक वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क की मौजूदा 40, 50 और 60 प्रतिशत मूल्यानुसार की दरों को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी और, मेरा मौजूदा आयात शुल्क रियायतों के क्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव है, ताकि इलेक्ट्रानिक उद्योग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कच्ची सामग्री और संघटकों की 13 नई मदें और पूंजीगत उपकरणों की 45 नई मदें इसके अन्तर्गत आ जाएँ। इन मदों पर लगने वाले सीमा शुल्कों की मौजूदा दरों को घटाकर, मशीनों तथा उपकरणों के मामले में, 35 प्रतिशत मूल्यानुसार करने, और कच्ची सामग्री और संघटकों के मामले में 55 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों से राजस्व को 13 करोड़ रुपए का निवल लान होगा।

108. ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मुक्त व्यापार क्षेत्रों के एककों के लिए अपने-आपने उत्पादन का निर्यात करना हमेशा सम्भव नहीं होता, और इन क्षेत्रों में निर्मित वस्तुओं के कुछ भाग को बेसी टैरिफ क्षेत्र में ले जाने की अनुमति देने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। यह फैसला किया गया है कि कुछ जतों के अन्तर्गत, किन्तु एकक के 25 प्रतिशत के बराबर उत्पादन को उपयुक्त शुल्कों की अवधिगी करके देश के अन्दर बिना किसी इस्तेमाल के लिए ले जाने की अनुमति दे दी जाए। इस प्रयोजन से सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियमों में संशोधन करने के लिए वित्त विधेयक में उपबन्ध किया जा रहा है।

109. जहाँ तक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों का सम्बन्ध है, विशेष उत्पाद-शुल्कों को 1982-83 में वर्तमान दरों पर जारी रखने का प्रस्ताव है। विशेष उत्पाद-शुल्कों में दी जाने वाली मौजूदा छूटों को भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

110. जैसाकि मैंने पहले कहा है, मेरा बुनियादी दृष्टिकोण यह रहा है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों से अतिरिक्त राजस्व अनिवार्यतः उत्पादन-वृद्धि से ही प्राप्त हो। मैं ऐसे उपायों का सहारा लेने से भी बच रहा हूँ जिसका बहुत सी वस्तुओं की खुरदरा कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है। अतः मैंने कराधान में वृद्धि के लिए केवल कुछ ही मदों को चुना है। इन मदों को चुनने समय, मैंने मांग और पूर्ति की स्थिति को, जिससे व्यापारियों का प्रभावित मुनाफा हुआ है, समूह लोगों के उपभोग की वस्तुओं पर उच्च दर से कर लगाए जाने की गुंजाइश और कतिपय बुनियादी उद्योगों पर लागू उत्पाद-शुल्कों और सीमा-शुल्कों के प्रति मैंने केन्द्र-बद्ध करने की आवश्यकता का ध्यान में रखा है।

111. सरकार ने सीमेंट के सम्बन्ध में "खेवी" और "खुली" बिकी की योजना और दोहरे मूल्य वाली नीति शुरू करने का निश्चय किया है। नई योजना का व्यापक सरकार द्वारा अग्रिम से अधिसूचित किया जा रहा है। जनवरी 1977 से सीमेंट के बुनियादी उत्पाद-शुल्क के स्तर में, जो

काफी नीचा है, कोई वृद्धि नहीं हुई है। यद्यपि इसके बाद से सीमेंट की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। मैं साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोझलाना सीमेंट, ब्लास्ट फर्न स्लैग सीमेंट और चिनाई के काम आने वाले सीमेंट पर कुल उत्पाद-शुल्क को 71.50 रुपए प्रति मेट्रिक टन से बढ़ा कर 135 रुपए प्रति मेट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूँ। सीमेंट की अधिक महंगी विशेष किस्मों पर ऊँची दरों पर शुल्क लगेगा। वषू सीमेंट संघों में उत्पादित सीमेंट पर लगने वाले कुल प्रभावी उत्पादन-शुल्क को 100 रुपए प्रति मेट्रिक टन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। मैं अभावित सीमेंट पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत का बुनियादी सीमा-शुल्क और उसके साथ पूर्ण प्रतिकार शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव करता हूँ। आयातित सीमेंट पर कोई महत्वपूर्ण शुल्क नहीं लगेगा। इन प्रस्तावों से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत 158.73 करोड़ रुपए और सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत 39.60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। उत्पाद-शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि के परिणामस्वरूप सीमेंट के 50 किलोग्राम के बोरे की कीमत में 3.175 रुपए की वृद्धि हो जाएगी।

112. पिछले कुछ समय से, धनी लोगों की पसन्द की कुछ महंगी इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ती हुई संख्या में किया जा रहा है। इस समय इन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत मूल्यानुसार 8 प्रतिशत की बहुत कम दर से शुल्क लगता है। अब मैं उत्पाद शुल्क टैरिफ में नई प्रविष्टियाँ करने बाँडियों कैसैड रिकार्डर्स और टी-प्रोड्यूसर्स, दूरदर्शन कैमरों और वीडियो कैमरों और ऐसी अन्य वस्तुओं पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत का बुनियादी उत्पाद-शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। स्पीयर और कैसैड किस्मों के खाली और भरे हुए वीडियो और श्रव्य टेपों और वीडियो डिस्क पर भी मूल्यानुसार 25 प्रतिशत का बुनियादी शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। उन टीनों और डिस्कों आदि को, जिन पर वाणिज्यिक प्रयोजनों से रिकार्डिंग न की गई हो, छूट प्राप्त होगी। मैं कीमत और संयोग के खेलों वाली इलेक्ट्रानिक मशीनों पर, जिनमें दूरदर्शन खेलों और वीडियो खेलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रानिक मशीनें भी शामिल हैं, 40 प्रतिशत की अपेक्षाकृत ऊँची दर पर बुनियादी शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इन प्रस्तावों से 3.83 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

113. उन प्रसाधन वस्तुओं पर, जिनमें अल्कोहल न पड़ा हो, मूल्यानुसार 100 प्रतिशत की बुनियादी दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाना है, जबकि ऐसी उन वस्तुओं पर, जिनमें अल्कोहल हो, औषधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ (उत्पाद शुल्क) अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यानुसार 60 प्रतिशत की दर से अथवा 13.20 रुपए प्रति लिटर विशुद्ध अल्कोहल घन की दर से, जो भी अधिक हो, उत्पाद शुल्क लगता है। ऐसा देखने में आया है कि इन विधेयों की कारण कुछ अनुचित लाभ उठाया गया है। इसलिए मैं वैकल्पिक मूल्यानुसार दर को बढ़ा कर 100 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि दोनों किस्मों की प्रसाधन वस्तुओं का मूल्यवर्धक रूप से एक समान रखा जाए। इस उपाय से 2.3 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है, जो राज्यों को मिलेगा।

114. माननीय सदस्यों को याद होगा कि मार्च, 1981 के बजट नीति प्रस्ताव में मानव-निर्मित रेशों और धागों पर लगने वाले राजस्व शुल्कों की समीक्षा करने की परिकल्पना की गई थी। यद्यपि कपड़े में कई का स्थान सर्वोच्च बना रहेगा, लेकिन यदि हमने कपड़ों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में मामूली सी वृद्धि करने के लिए, आयोजना में रखे गए लक्ष्य को भी प्राप्त करना है तो कई और मानव-निर्मित रेशों और धागों के मिश्रणों के उपभोग में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देना जरूरी है। पिछले कुछ समय से, ऐसे कैंडिड कपड़े, जिनमें पालिग्रेटर रेशों का अनुपात इतना कम होता है कि उनके कपड़ों में प्रवेक्षित टिकाऊपन नहीं आ सकता और न ही उन में घासानी से पहने जाने वाले घुलारि के गुण आ सकते हैं, बाजार में खूब मात्रा में आ रहा है, जिन पर ऐसी मोहूर्तें लगी हैं जिन से जनता को धोखा दिया जा सकता है। पालिग्रेटर रेशों का बेहतर उपयोग करने की दृष्टि से यह जरूरी है कि बाह्य अनुपात के

ब्लैंड वाले कपड़ों को प्रोत्साहन दिया जाये और ऐसे ब्लैंड वाले कपड़ों के उत्पादन को निरुत्साहित किया जाए जिनसे वास्तव में अभीष्ट प्रयोजन पूरा नहीं होता। इसलिए मैं मानव-निर्मित रेशों और धागों पर लागू करों में कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव करता हूँ। मैं ब्लैंड सूती धागे और सेलूलोसी स्पन धागे पर, जिसमें भार के अनुपात में छठा हिस्सा पालि-एस्टर रेशे का हो, वर्तमान 1.63 रुपए प्रति किलोग्राम के कुल भौगत शुल्क भार को बढ़ाकर 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव करता हूँ। ऐसे ब्लैंड धागे पर जिनमें छठे हिस्से से अधिक लेकिन 50 प्रतिशत से कम पालि-एस्टर रेशा हो, और जो भारतीय परिस्थितियों के लिए वांछनीय ब्लैंड हो, शुल्क का कुल भार 22.50 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 11.25 रुपए प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार 50 प्रतिशत भ्रमवा उससे अधिक, लेकिन 70 प्रतिशत से कम के पालि-एस्टर रेशे वाले ब्लैंड कपड़े पर शुल्क के भार को 30 रुपए प्रति किलोग्राम से घटा कर 22.50 रुपए प्रति किलोग्राम किया जा रहा है। 70 प्रतिशत से अधिक पालि-एस्टर रेशे के ब्लैंड वाले कपड़े के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

115. एक्जिलिक रेशे पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के कुल भार को 12.50 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 17.50 रुपए प्रति किलोग्राम करने और इसके साथ-साथ प्रायानि रेशे पर प्रतिकारी शुल्क को 37.50 रुपए से घटा कर 30 रुपए प्रति किलोग्राम कर देने का प्रस्ताव है।

116. अब मैं विस्कम स्टेपल रेशे की तरफ आता हूँ। इस पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को 3.125 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 4.00 रुपए प्रति किलोग्राम किया जा रहा है और पोलोनोमिक तथा हाई वेट माइलम रेशे पर उत्पाद-शुल्क को 5.00 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 4.00 रुपए प्रति किलोग्राम किया जा रहा है।

117. एमिटेड फिलामेंट धागा, जो बिकेन्द्रीकृत सेक्टर में हस्तेमान किया जाता है, देश में पर्याप्त मात्रा में तैयार नहीं किया जाता। इस धागे के आयात को सरल बनाने के लिए इस पर लगे 125 प्रतिशत सीमा-शुल्क को घटाकर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव है।

118. मेरा अन्य रेशों, जैसे एमिटेड रेशे और पालि-एस्टर रेशे तथा अन्य फिलामेंट धागों जैसे विस्कम नाइलन और पालि-एस्टर फिलामेंट धागों पर लागू उत्पाद-शुल्क या बुनियादी सीमा-शुल्क में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

119. इन प्रस्तावों से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों में 13 करोड़ रुपए की निवल हानि होगी और सीमा-शुल्कों में 12.94 करोड़ रुपए का लाभ होगा।

120. फिलहाल, मानव-निर्मित कपड़ों पर कोई बुनियादी उत्पाद-शुल्क नहीं लगना क्योंकि ऐसे शुल्क रेशों और धागों पर लगे हुए हैं। इन कपड़ों पर बिक्री-कर के बदले केवल अनिश्चित उत्पाद-शुल्क लगता है। यद्यपि उन कपड़ों के मामले में, जिनका कारखाना बाह्य मूल्य 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक होता है, वर्तमान उत्पाद-शुल्क की दरें उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं, लेकिन ऊंची कीमत के कपड़ों के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क की दर एक समान 5½ प्रतिशत मूल्यानुसार है। कीमतों के इस वर्ग में ऐसे बहुत से ऊंची कीमतों के कपड़े हैं जो समाज के समूह लोगों द्वारा हस्तेमान किए जाते हैं और इसलिए इन कपड़ों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्कों में साधारण-सी वृद्धि की जा सकती है भन्ना, मैं शुल्क दर के ढांचे में इस प्रकार वृद्धि करना चाहता हूँ जिससे 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर से अधिक के कारखाना बाह्य कीमतों वाले कपड़ों पर 7½ प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क लगा दिए जाएं। इस प्रस्ताव से 35 करोड़ रुपए के अनिश्चित राजस्व का अनुमान है जो राज्यों को मिलेगा। यह प्रस्ताव राज्यों के प्रति केन्द्र की वचनबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक और कदम होगा जिसके अनुसार विकासियों के मूल्य के प्रतिशत के रूप में बिक्री-कर के बदले लगाए जाने वाले अनिश्चित उत्पाद-शुल्क के

समूचे अनुपात में वृद्धि की जाएगी। मुझे विश्वास है कि संसद और राज्य इस कदम का हार्दिक स्वागत करेंगे।

121. सूत, सेल्यूसोसी और पालि-एस्टर के ब्लैंड कपड़ों पर उत्पाद-शुल्कों में जो परिवर्तन किए गए हैं, उनका कुल प्रभाव यह होगा कि वांछनीय ब्लैंडों के कपड़े की कीमतें कम हो जाएगी और कम वांछनीय ब्लैंडों के अन्य कपड़ों की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी।

122. मैंने टैरिफ नाम-सूची का समीकरण करने और उसमें अधिक स्पष्टता लाने और इस प्रकार वर्गीकरण सम्बन्धी विवादों की गुंजाइश को न्यूनतम करने के उद्देश्य से विषय त्रिधैयक में कुछ उपबन्ध किए हैं। ये उपाय राजस्व में वृद्धि करने के लिए नहीं किए गए हैं। लेकिन वर्गीकरण में परिवर्तन होने के कारण कुछ राजस्व प्राप्त होगा। इन प्रस्तावों के अन्तर्गत, अन्य वस्तुओं के साथ-साथ मुख्य पेट्रोलियम उत्पाद, कृत्रिम और संश्लिष्ट रेसिन एवं प्लास्टिक सामग्री आ जाएगी।

123. मेरा कागज और गते से सम्बन्धित शुल्क दरों को युक्ति-संगत बनाने और उनके ढांचे में परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे पैमाने पर कागज का संपरिवर्तन करने वालों को उत्पाद शुल्क की प्रभावशीलता से छूट देना और उन्हें उत्पाद शुल्क नियंत्रण से मुक्त करना है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व में होने वाली हानि का पूरा करने के लिए, मैं औद्योगिक किस्मों के कागज और गते पर बुनियादी उत्पाद-शुल्क में 2½ प्रतिशत मूल्यानुसार की थोड़ी सी वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। लेकिन कुछ उच्च मूल्यवर्धित वर्गों वाले संपरिवर्तित कागजों पर 32½ प्रतिशत मूल्यानुसार का बुनियादी उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, कागज और गते की बनी विभिन्न वस्तुओं को टैरिफ सवों की परिधि में लाने का प्रस्ताव है; लेकिन शुल्क को प्रभावकारी ढंग से मुद्रित कार्टनों और मुद्रित डिब्बों तक ही सीमित रखा जाएगा।

124. हाल के वर्षों में, निवेश्य वस्तु उत्पाद शुल्क राहत की योजना कुछ विनिर्दिष्ट औद्योगिक उत्पादों पर भी लागू कर दी गई है। मैं निवेश्य वस्तु उत्पाद शुल्क सम्बन्धी इस राहत को संश्लिष्ट रबर, कार्बन ब्लैक और टायरों के उत्पादन में काम आने वाले रबड़ को संसाधित करने वाले रसायनों पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं राजस्व की हानि को पूरा करने के लिए, टायरों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को 60.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 66 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ। हालांकि टैक्टरों और स्कूटरों के टायरों को भी निवेश्य वस्तु उत्पाद शुल्क राहत का लाभ मिलेगा, लेकिन मेरा उन पर प्रतिशत शुल्क की दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं है। चूंकि इसका आशय मनुष्यन बनाए रखना है, इसलिए इससे कोई अनिश्चित राजस्व प्राप्त नहीं होगा।

125. जैसा कि सब को मालूम है, एल्यूमीनियम धातु की निर्धारित कीमत, निवेश्य वस्तुओं की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर बढ़ा दी जाती है। उत्पाद शुल्क के भार को सीमित रखने के लिए, मात्रानुसार शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। वरं इस प्रकार होंगे : इलेक्ट्रो-लिट्रिक ग्रेड के बलों पर 3085 रुपए, सिलिसियों (जिनेट) पर 3125 रुपए प्राथमिक उत्पादों द्वारा उत्पादित तार की छड़ों पर 3330 रुपए और तार छड़ों पर 3280 रुपए। प्रतिकारी शुल्कों की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस प्रस्ताव से राज्य विजली बोर्डों को कुछ राहत मिलेगी।

126. करों से बचने को रोकने के उपाय के रूप में, चपटे (प्लेट) कांच पर वर्तमान मूल्यानुसार शुल्क के साथ-साथ प्रति मिनीमीटर मांटे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 5.50 रुपए की दर से मात्रानुसार शुल्क भी लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। चपटे कांच की विभिन्न किस्मों के लिए शुल्क की प्रभावी दरें निचले स्तर पर निर्धारित की जा रही हैं।

127. सरकार को ब्रांड वाला और बिना ब्रांड की वीडियों पर लागू उत्पाद शुल्क की वर्तमान विधेदी दरों के कारण बीड़ी उद्योग में कटाव का

आरोग्य लगाने वाले अभ्यावेदन बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। कई राज्य सरकारों और संघों ने अनुरोध किया है कि यह क्षेत्र समाप्त किया जाना चाहिए। इसी किस्म का सुक्ष्म श्रम मंत्रियों की हानि में हुई एक बैठक में भी दिया गया है। इन बातों का ध्यान में रखते हुए मैं शुल्क की वर्तमान विवेदी दरों को समाप्त करने और ब्रांड वाली तथा बिना ब्रांड की दोनों किस्मों की बीड़ियों पर 3.60 रुपए प्रति 1000 की समान दर से मिला-जुला शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके साथ-साथ, शुल्क से छूट की हकदार बिना ब्रांड की बीड़ियों की वर्तमान मात्रा भी एक विंता बी में 30 लाख से घटा कर 20 लाख की जा रही है। इसके बावजूद, आय-नियोजित पारिवारिक यूनिट, छोटे दुकानदार आदि अब भी कर के जाल से बाहर रहेंगे।

128. 72 विनिर्दिष्ट वस्तुओं की वस्तुओं के छोटे निर्माताओं पर लागू सामान्य उत्पाद शुल्क नियोजन योजना एम्बेस्ड्ड ग्रेड और धागे के निर्माताओं पर भी लागू की जा रही है। यह देखा गया है कि अनिज जल (एम्बेडेड वाटर) के लोकप्रिय ब्रांडों पर उत्पाद शुल्क से बचने के लिए इस योजना का कुछ दुरुपयोग किया गया है। इसलिए, मैं एम्बेडेड वाटर को इस सामान्य योजना के क्षेत्र से बाहर लाने और इसके लिए नई योजना बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। लेकिन, छोटे निर्माताओं को, जो अपने उत्पादों की किसी आने ब्रांड या व्यापारिक नाम से करते हैं, निश्चय ही वर्तमान योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ प्राप्त होता रहेगा। लेकिन ऐसे निर्माता जो किसी ब्रांडों या व्यापारिक नामों के मासिकों के साथ किए गए करों के अनुसार किसी ब्रांडों या व्यापारिक नामों के अंतर्गत एम्बेडेड वाटर का उत्पादन करते या दोनों में अरने का काम करते हैं, यह रियायत पाने के हकदार नहीं होंगे। यह भी विशेष रूप से करों से बचने को रोकने का उपाय है।

129. इसी प्रकार यह प्रतीत होता है कि उस सामान्य योजना का जिसका जिक्र पहले किया गया है, संश्लिष्ट कार्वनिक रंजक पदार्थों के कुछ छोटे निर्माताओं द्वारा कुलपयोग किया गया है। वर्तमान योजना के अंतर्गत 7½ प्रतिशत लाख रुपए तक की निकासी के लिए पूरी छूट दी जाती है और अनिजित 7½ लाख रुपए पर संगठित सेक्टर पर लागू शुल्क दर के तीन-चौथाई की दर से शुल्क लगता है। रंजक पदार्थों पर शुल्क की अपेक्षाकृत ऊँची दर को देखते हुए और इस बात का ध्यान में रखते हुए कि कुछ रंजक पदार्थों के उत्पादन की तकनीक तुलनात्मक रूप से सरल है, ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे एककों की संख्या बहुत बढ़ गई है, जिसके परिणामस्वरूप मर्यादित पर और कुल मिलाकर उद्योग पर और निर्यात पर भी हानिकर प्रभाव पड़ा है। इसलिए, मैं रंजक पदार्थों की सामान्य योजना की परिधि से बाहर निकासन का प्रस्ताव करता हूँ। एक नई योजना के अंतर्गत जो रंजक पदार्थों के सम्बन्ध में घोषित की जा रही है, बहुत छोटे निर्माताओं को जिनकी निकासी 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होगी, उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी। अन्य छोटे निर्माताओं के मामले में, 15 लाख रुपए तक के रंजक पदार्थों की निकासी पर संगठित सेक्टर के लिए लागू शुल्क की 50 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा। सभी निर्माताओं का उत्पाद शुल्क के नियंत्रण के अधीन लाया जाएगा। राहत की वर्तमान योजना के मौखिक तत्व को, कुल मिलाकर, नई योजना के अंतर्गत भी कायम रखा गया है।

130. इस समय, सधु सेक्टर, निर्मित विनिर्दिष्ट उपभोग्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर सामान्य दरों से कम दरों पर शुल्क लगाया जाता है। शुल्क की इस रियायत को वास्तविक छोटे निर्माताओं तक सीमित रखने के लिए शुल्क में छूट की इस योजना को उन निर्माताओं तक सीमित रखने का प्रस्ताव है, जिनका कुल वार्षिक कारबार 2 करोड़ रुपए से अधिक न हो।

131. जहाँ तक दियासलाई उद्योग का संबंध है, मेरा वर्तमान शुल्क ढाँचे में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये छोटे निर्माता, जिनकी निकासी पिछले वित्तीय वर्ष में 18 करोड़ दियासलाई से अधिक नहीं थी, वित्तीय वर्ष में 12 करोड़ दियासलाई तक की निकासी पर

प्रति गुरुस डिब्बियों पर 1.60 रुपए के शुल्क की रियायती दर के हकदार बने रहेंगे। यदि दियासलाई उन निर्माताओं के पत्रों के अंतर्गत बाजार में बेजी जाएगी। जो 4.50 रुपए या 7.20 रुपए की दर से शुल्क अदा करते हैं तो यह रियायत नहीं दी जाएगी।

132. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, सरकार उत्पाद शुल्क राज का उपयोग दियासलाई उद्योग के कुटीर सेक्टर के विकास की प्रबल प्रोत्साहन देने के लिए करती रहा है। लेकिन दरमियाने सेक्टर को कई निर्माताओं ने कुटीर सेक्टर का उत्पाद शुल्क में रियायत देने की स्कीम को व्यायालयों में चुनौती दी है और अपने हक में फैसला ले निकले हैं। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान सेक्टर के एककों को शुल्क का बहुत बड़ा राशिओं को वापसी करनी पड़ सकती है। कृति ऊँची दर के शुल्क के भार को करोड़ों उपभोक्ताओं पर गहने हैं। डाला जा चुका होगा, इसलिए, उन शुल्कों की वापसी का परिणाम केवल यह होगा कि इस सेक्टर के निर्माता अनुचित रूप से धनी हो जायेंगे। दग गोपावना को रोकने के लिए वित्त विधेयक में उपबन्ध किया गया है।

133. निकट भूत में यह शुल्क कौमल से उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्धारण मूल्य को तब कथन के त्वर में कुछ विवाद उत्पन्न हो गए थे, जिनके कारण काफी मुश्किलें ब्रांजें हुई। इसके परिणामस्वरूप राजस्व की काफी बड़ी राशि प्रक्षुब्ध हो गई। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 3 में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि यह शुल्क कौमल से कटौती-योग्य उत्पाद शुल्क की राशि को गणना करते समय निर्धारण के अधीन वस्तुओं पर देय प्रभावी उत्पाद शुल्क की रकम को ही हिसाब में लिया जाएगा। इस संशोधन का 1 अक्टूबर, 1975 की पिछली तारीख से लागू किया जा रहा है।

134. यह काफी दूर से चली आ रही प्रणाली है कि किर्मा कारखाने के अन्दर उपभोग (केप्टिव कन्जम्पशन) के लिए इन्फोमल की गई ऐसी वस्तुओं पर, जिनका उत्पादन अभी कारखाने में किया गया हो, उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है। लेकिन कुछ उच्च व्यायालयों के फैसले के परिणामस्वरूप, यह स्थिति कुछ संविध बन गई थी; इन फैसलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के कुछ उपबन्धों का अर्थ-निर्णय करते हुए यह निर्णय लिया गया था कि ऐसी वस्तुओं पर शुल्क वसूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे वस्तुएं कारखाने से 'ब्रूट' नहीं गई थी; कई निर्माताओं ने इसी बातों के आधार पर व्यायालयों से स्थगन यादेश भी प्राप्त कर लिए हैं। इस मामले में अपना की गई है। लेकिन स्थिति को अतिरिध बनाने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के संगत नियमों को उपयुक्त रूप से संशोधित कर लिया गया है। वित्त विधेयक में भी ऐसा उपबन्ध कर दिया गया है जिससे ये संशोधन पिछली तारीखों से लागू होंगे और मौजूदा पद्धति के अनुसार शुल्क की जो वसूलियाँ की गई थी, वे विधिमन्य हो जायेंगी।

135. जैसाकि मदन का ज्ञात है, प्रधान मंत्री द्वारा वर्ष 1982 को 'उत्पादकता वर्ष' की संज्ञा दी गई है। आशा है कि बुनियादी ढाँचे की सुविधाओं में सुधार होने से चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में और वृद्धि होगी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजस्व तंत्र का विवेकपूर्ण ढग से उपयोग किया जा सकता है। इस उद्देश्य से, मेरा 1 मार्च, 1982 में शुरू होने वाली और 28 फरवरी, 1983 को समाप्त होने वाली 12 महीनों की अवधि में वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्पाद शुल्कों में रियायतें देने की एक योजना बनाने का प्रस्ताव है। इस योजना में 38 टैरिफ मदें शामिल होंगी, जिनमें बुनियादी कच्चा माप, अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक निवेध वस्तुएं और कुछ तैयार वस्तुएं शामिल होंगी। इनमें से कुछ वस्तुएं ये हैं : कास्टिक सोडा, उर्वरक, संश्लिष्ट रेजिन, इस्पात के डाले और इस्पात के उत्पाद, अलतवेहन इजन, तार और कंबल दो और तीन पहियों वाले मोटर वाहन, हल्की और भारी यांत्रिक गाड़ियाँ, ट्रेक्टर, रेलवे वाहन, मानव-निर्मित रणे और फिनमेट यार्न, टायर

घरों लिखाई और छाई का कागज। पूरी सूची बजट-पत्रों में देखी जा सकती है। इस योजना के लाभ केवल उन मामलों में प्राप्त होंगे जहाँ उपर्युक्त 12 महीनों की अवधि में उत्पादन, आधार अवधि अर्थात् 28 फरवरी, 1982 को समाप्त होने वाले - 12 महीनों में हुए उत्पादन के 110 प्रतिशत में वृद्धि होगी। ऊपर बताए गए तरीके से संगठित आंतरिक उत्पादन पर शुल्क की रियायत, उन वस्तुओं के मामले में, जिनके शुल्क की दर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत अवधि उसने कम है, अर्थात् कि, नए शुल्क की कुल राशि के 1/5 के बराबर और अन्य वस्तुओं के मामले में अर्थात् नए शुल्क के 1/10 के बराबर की जाएगी। समूची अवधि के लिए इस प्रकार संगठित राशि जमा के रूप में रखी जाएगी और उनका उपयोग 1983-84 के वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छमायवी के लिए किया जा सकता है।

136. यह योजना छोटे पैमाने के निमाताओं पर भी लागू होगी जो वास्तव में शुल्क भुगत करते हैं। यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि ऐसे छोटे एकक जो संगत उत्पाद शुल्क रियायत स्कीमों के लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं और जो 1981-82 में सम्बन्धित कट प्राफ प्वाइंट के अन्तर्गत आते हैं, 1983-84 में भी उक्त लाभ प्राप्त करने के पात्र रहेंगे, चूँकि वे उत्पादकता वर्ष में पात्रता की सीमाओं से अधिक वस्तुओं का उत्पादन और निकासी करने हों।

137. मुझे विश्वास है कि उद्योग अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और सरकार की इस उदारता के प्रति उनकी प्रतिक्रिया अनुकूल होगी तथा वे उत्पादन के नए शिखर प्राप्त करेंगे। चूँकि अधिक उत्पादन से सरकार को भी उत्पाद शुल्कों की अधिक प्राप्ति के रूप में लाभ होगा, इसलिए मैं प्रस्तावित रियायत के कारण राजस्व में कमी होने की चिन्ता में नहीं ले रहा हूँ।

138. मैंने पहले ही समाज के दरमियानी वर्गों के और गरीब वर्गों पर अपने प्रस्तावों के प्रभाव को कम से कम करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। इस विषय में, मैं और आगे जाने तथा उन वस्तुओं पर कुछ रियायतें देने का प्रस्ताव करता हूँ जिनका उन वर्गों से विशेष सम्बन्ध है। मैं ग्राम उपयोग की कई वस्तुओं को उत्पाद शुल्कों से आंशिक या पूर्ण रूप से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। इनमें से कुछ उत्पाद छात्रों से सम्बन्धित हैं और कुछ सामान्य उपयोग के हैं और कुछ ऐसे हैं जो ग्रामों के काम के हैं और इनमें से एक वस्तु ऐसी है जो बाघवती के काम की है। मैं लेमिनों ड्रेजर्स, पैनों और बाल प्वाइंट पैनों और रिफ्लेक्टर्स, प्रयोगशाला में काम आने वाले कांच के सामान, इंसुलन के बत्तियों, धूम्र तालासों और उनके हिस्सों, वाटर कूलर्स मोस बत्तियों, दूध द्रवों, बर्तनों और चम्मचों के केमों, एक दिन के शालासों वाली घड़ियों, घरेलू पानी फिल्टरों, हैड पम्पों, ब्रेव टाइपराइटरों, ग्रामों के लिए गाड़ियों और हेल्मेटों को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, मैं फलों और सब्जियों के विभिन्न उत्पादों पर बुनियादी उत्पाद-शुल्कों को 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं पूरी छूट के प्रयोजन से श्रुतों के प्रति से घटाकर 10 प्रतिशत जोड़े की वर्तमान कीमत को 15 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति जोड़ा करने का प्रस्ताव करता हूँ। लाख को भी पूरी छूट दी जा रही है। दूध को लेमिनेटिड कागज के पैकटों में बँधे जाने में पैक करने की लागत को कम करने के उद्देश्य से, मेरा कागज के इन पैकों के निर्माण में भारतीय डेरी कारपोरेशन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कागज और कम वनस्पत वाली पोलीथीलीन फिल्म को उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है। इस उपाय से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में दूध का विपणन पैपर पैकों में किया जा सकेगा, जिसकी शेलक प्रायः अपेक्षाकृत अधिक लम्बी होती है; इससे दूध की अधिक पैदावार वाले मौसमों में उत्पादित अतिरिक्त दूध का पूरा उपयोग करने में भी सहायता मिलेगी।

139. इस समय 75 सी. सी. तक की इंजन क्षमता वाले मोपेडों पर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार की घटी हुई दर पर उत्पाद शुल्क लगता

है। इंजन की बचत करने वाला यह वैयक्तिकृत वाहन विशेष रूप से गहरी और अर्ध-गहरी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर अधिकाधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। मैं 100 सी. सी. तक की इंजन क्षमता वाले मोपेडों को भी यह रियायत देने का प्रस्ताव करता हूँ। यह प्रस्ताव की जाती है कि उनसे इंजन की और अधिक बचत होगी।

140. मैंने इससे पहले मानव-निर्मित रेलों और प्राणों पर सगे राजस्व शुल्कों की समीक्षा के परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्कों और सीमा शुल्कों में किए गए कतिपय समायोजन का उल्लेख किया था। इन नए व्यवस्था सेक्टर में लगभग 120 लाख मीटर कैंडेड कपड़े का उत्पादन होता है। इस उद्देश्य से कि हथकरवा सेक्टर के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो सके, मैं हथकरवा पर बुने गए पालिस्टर मिश्रित कपड़े की प्रोमोशिंग की अवस्था में लगने वाले उत्पाद शुल्कों से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ, यदि उनका प्रोमोशिंग राज्यों के हथकरवा विकास निगमों द्वारा प्रयास इन सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित गौरी सूतारी समितियों द्वारा एवांचन कारखानों में किया जाए। इस रियायत से राजस्व में 4 करोड़ रुपए की कमी होगी। इस बात को देखते हुए कि मानव निर्मित मेटलाइड फ्लायमेड धागे का इस्तेमाल साड़ियों और ऐसे ही अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है, मैं इस धागे को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। इस रियायत का मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए है।

141. मैंने उत्पाद शुल्कों सम्बन्धी जिन रियायतों का अर्थ-समी उल्लेख किया है, उनसे राजस्व में पूरे एक वर्ष में कुल 13.77 करोड़ रुपए की कमी होगी।

142. जिन मामलों में 28 फरवरी, 1982 से प्रभावी अधिसूचनाओं के अतिरिक्त परिवर्तन किए जाते हैं उनमें अधिसूचनाओं की प्रतियाँ यथा समय सभी पटल पर रख दी जाएँगी।

143. मेरे प्रस्तावों से उत्पाद शुल्कों से 198.18 करोड़ रुपए और सीमा शुल्कों से 391.35 करोड़ की निवल प्राप्ति होगी। औद्योगिक और प्रसाधन निमित्तियाँ (उत्पाद शुल्क) अधिनियम के अन्तर्गत शुल्कों से एक पूरे वर्ष में 2.30 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। इन सभी प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में, कुल मिलाकर, कोष की 497.60 करोड़ रुपए और राज्यों की 102.23 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति होगी।

144. अब मुझे अपने सम्मानित सहयोगी, संचार मंत्री की ओर से कुछ कहना है। जैसाकि सचन की जात है, पिछले कई वर्षों के दौरान डाक सेवाओं का विस्तार समूचे देश भर में कर दिया गया है देश में 1,40,000 से अधिक डाकघर हैं। यह एक भारी रोजगार-प्रधान सेवा है। इसके अन्तर्गत 5.6 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें विभागेतर कर्मचारी भी शामिल हैं। इसलिए डाक विभाग के चलाने व्यय में वेतन और मजदूरी का भाग बहुत बड़ा है। इस समय डाक सेवा बहुत कम मूल्य पर प्रदान की जाती है और वरें बहुत सी सेवाओं की प्रत्यक्ष लागत को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। महंगाई भरे की अतिरिक्त किस्तों के लिए जाने और अन्य प्रचालन व्ययों में वृद्धि हो जाने से इन लागतों में और भी अधिक बढ़ोतरी हो गई है। इसलिए भुविट पोस्ट कार्ड की कीमत को 20 पैसे से बढ़ाकर 25 पैसे, लैटर कार्डों की कीमत 25 पैसे से बढ़ाकर 35 पैसे और सबसे कम भार-खंड वाले लिफाफों की कीमत को 35 पैसे से बढ़ाकर 50 पैसे करने का प्रस्ताव है। साधारण पोस्ट कार्ड की, जिसका इस्तेमाल सामान्य तौर पर ग्राम प्रायमी द्वारा किया जाता है, दर में कोई वृद्धि नहीं होगी, हालांकि इस सेवा से प्रति वर्ष लगभग 20 करोड़ रुपए की हानि होती है। बुक-पोस्ट की वस्तुओं के शुल्क को भी 25 पैसे से बढ़ाकर 30 पैसे करने का प्रस्ताव है। कई वर्षों से एक रजिस्टर्ड समाचार पत्र की डाक दर 2 पैसे के बहुत निचले स्तर पर बनी हुई है। इसे ऊँचे भार-खंडों के लिए यथोचित समायोजनों के साथ, एक साम-चार पत्र के लिए 5 पैसे निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इस वृद्धि के बावजूद, समाचार पत्र सेवा से प्रति वर्ष 7 करोड़ रुपए तक की हानि होगी।

145. प्रस्तावित शुल्कों की जानकारी देने वाला एक ज्ञापन बजट-पक्षों के साथ परिचालित किया जा रहा है। ये परिवर्तन संसद द्वारा वित्त विधेयक को पारित कर दिए जाने के बाद अधिसूचित की जाने वाली तारीख में लागू होंगे। इन परिवर्तनों से एक पूरे वर्ष में 35.33 करोड़ रुपए की और 1982-83 में लगभग 26 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है।

146. मैंने बताया था कि कराधान की मौजूदा तरों पर बजट का घाटा 2085 करोड़ रुपए होगा। अब प्रस्तावित विभिन्न कर उपायों तथा राहतों और रियायतों में, कुल मिलाकर, 1982-83 के दौरान केन्द्र को 470 करोड़ रुपए का और राज्यों को 63 करोड़ रुपए का निवल प्रतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। हमारे अलावा, राज्यों को औषधीय और प्रसाधन सामग्री पर शुल्क में बढ़ि किए जाने से 2 करोड़ रुपए से अधिक का प्रतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। मैं पूँजी निवेश बांधों से, जिनका उल्लेख मैंने पहले किया था, 250 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान लगा रहा हूँ। इससे 1982-83 में 1365 करोड़ रुपए का घाटा बच जाएगा, जिसकी पूर्ति के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, और जो चालू वर्ष के अनुमानित घाटे से काफी कम है।

147. अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्थ-व्यवस्था में अधिक बचत, निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से नीतियों का एक ढांचा प्रस्तुत किया है। आयोजना परिषद में विशेषतः उन सेक्टरों को आयोजना परिषद में भारी वृद्धि की गई है, जिन पर 20-सूची कार्यक्रम में बल दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इन सभी खर्चों के बावजूद, बजट के घाटे को उचित सीमा से बढ़ने नहीं दिया गया है। ऐसा करने के लिए माघस जुटाने के उपाय करना अपरिहार्य था। फिर भी, मैंने यह ध्यान रखा है कि नए साधन मूद्रास्फीतिकारी बजाज वाले बिना जुटाए जाएं। मैंने विशेष रूप से कम और मध्यम आय वर्गों पर बोझ डालने से बचने की कोशिश की है। यह बजट उन सब के लिए चुनौती है, जो हमारी विकास आयोजना को क्रियान्वित करने से सम्मथित हैं। इसके जरिए किमनों, उद्योगों और श्रमिकों को उत्पादन बढ़ाने, व्यापारियों को स्वस्थ विपणन और वितरण की सुनिश्चित व्यवस्था करने और वस्तुतः हमारी सारी जनता, सैनिकों और नागरिकों को राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा के दोहरे कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का प्रामाण्य दिया गया है।

148. महोदय, इन शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ।

ए० सी० तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Budget Division)

Budget 1982-83

Speech of

MINISTER OF FINANCE
New Delhi, the 27th February, 1982

PART A

Sir,

I rise to present the Budget for the year 1982-83.

2. The Economic Survey for 1981-82, placed before the House a few days ago, gives a detailed review of the current trends in the economy. I shall, therefore, touch upon only a few important aspects of the economic situation which have influenced the formulation of this year's Budget.

3. As the House is aware, when the present Government came into office a little over two years ago, the country was faced with a serious and deteriorating economic situation. Gross National Product had declined by as much as 4.8 per cent in 1979-80, the infrastructure was in shambles, and prices had increased at an annual rate of 23.3 per cent by the end of January, 1980. It was against this background that, while presenting the regular Budget for 1980-81, my distinguished predecessor had informed the House that an important task before the Government was to arrest the deterioration in the economic situation and to set the economy on the path of stability and growth.

4. I am glad to say that we have gone a long way in achieving these objectives. Our Gross National Product in real terms increased by 7.5 per cent in 1980-81, and is expected to grow further by 4.5 per cent in 1981-82. The infrastructure is functioning well. Inflation is being controlled. Production of foodgrains is likely to reach a new peak this year. The industrial sector will record a growth of 8 per cent.

5. The fight against inflation has been a high priority of the Government. Any slackening of effort on this front would have undermined the very basis of our development. Inflation hurts all sections of the community, but it hurts the weaker and poorer sections the most. Inflation also hurts the development process as investment costs get distorted, and financing becomes an increasingly severe problem. It is, therefore, a matter of satisfaction that we have succeeded in bringing down the rate of inflation substantially.

6. At the end of January, 1982, the annual rate of inflation on a point-to-point basis was only 4.9 per cent as against 15.9 per cent at the end of January, 1981 and 23.3 per cent at the end of January, 1980 when the present Government took over. The deceleration in the wholesale prices has occurred in a wide range of commodities, and is being gradually reflected in the consumer price index.

7. However, the price situation requires constant vigilance, and there can be no room for complacency. The international price situation continues to be uncertain. At home, a drought or the failure of a major crop may well upset the demand and supply balance. We must continue our efforts to increase the supplies of agricultural and industrial commodities and also restrain the growth of aggregate demand. At the same time, we must ensure that anti-social elements do not disrupt supplies and the distribution network.

8. As I mentioned before, foodgrains production is likely to reach a new peak in the current year. The kharif foodgrains production is estimated at around 80 million tonnes as against 77.4 million tonnes in 1980-81, and the prospects of rabi crop are good. Sugarcane production is likely to increase substantially and sugar production should reach a record level of over 67 lakh tonnes. Groundnut production may be 20 to 25 per cent higher than in the last year. Significant increases are also expected in cotton and jute.

9. The sustained good performance in agriculture is testimony to the hard work of our farmers, agricultural scientists, and extension workers. It also underscores the basic soundness of our agricultural strategy, which has emphasised creation of irrigation potential, greater fertiliser use, spread of high-yielding varieties of seeds, and remunerative price support policies.

10. Industrial production, which had declined by 1.4 per cent in 1979-80, recorded an increase of 4 per cent in 1980-81. In 1981-82, the growth rate will be twice as high. A large number of industries such as petroleum and petroleum products, fertilisers, steel, cement, vanaspati, sugar, newsprint, caustic soda, wagons and commercial vehicles, are expected to achieve new peak levels of production during the year. The increase in industrial production has been sustained by the concerted action taken by the Government to improve the performance of infrastructure sectors. In the current financial year, upto January, power generation has increased by 11.3 per cent. Coal production in the last two years has increased by over 17 million tonnes, and the target of 121 million tonnes for 1981-82 is likely to be exceeded. In railways, the previous record in freight loading will be

surpassed and the revenue earning traffic is expected to go up to 165 billion tonne kilometres. This has been made possible by improvement in operational efficiency as evidenced, for example, by the significant reduction in the wagon turn-round time during the year.

11. Monetary and credit policies during the year continued to emphasise the requirements of meeting the credit needs for higher production, particularly in the priority sectors, while restraining the growth of aggregate demand. In order to restrain the growth of liquidity in the system, the cash reserve ratio was increased in phases from 6 to 8 per cent, and the statutory liquidity ratio was raised from 34 to 35 per cent. The Bank Rate was increased from 9 to 10 per cent and refinancing rates of the RBI were also raised. Even so, the growth of bank credit to the commercial sector during the year 1981-82 is likely to be of the order of 19 per cent which should be adequate to meet the legitimate credit requirements of productive sectors.

12. Hon'ble Members will be happy to note that the operation of our public sector banks has been further oriented towards extending banking facilities to underbanked rural and semi-urban areas, and enlarging the flow of credit to priority sectors particularly the weaker sections of society. During January–November, 1981, 2517 new branches were opened by commercial banks of which 2269 were in rural and semi-urban areas. During 1981, 22 regional rural banks were added to 85 such banks as at the end of 1980. The priority sectors now account for about 36 per cent of the aggregate bank credit as compared to about 33 per cent in 1979. The target to be achieved by March, 1983 is 40 per cent. The differential rate of interest scheme has been effectively implemented and the target of 1 per cent of aggregate credit for this scheme is being achieved by public sector banks. The National Bank for Agricultural and Rural Development is expected to start functioning within the next few months. I am also pleased to inform the House that the Export Import Bank of India has been established with effect from 1st January, 1982.

13. I would now like to refer to the balance of payments situation. As the House is aware, there has been a substantial deterioration in our balance of payments since 1979-80 primarily because of sharp increases in import prices, particularly of oil and oil products. Anticipating these developments, the Government made timely arrangements to negotiate a line of credit for SDR 5 billion from the International Monetary Fund under its Extended Fund Facility. This was necessary to avoid the disruption of our economy for want of essential imports and to gain time for re-adjustment to the new situation. This line of credit has been accepted in order to support an adjustment programme drawn from our strategy of planned development. It will help us to implement our own policies which have been sanctioned and approved by our people and Parliament.

14. The main elements of the Government's strategy for restoring the viability of our balance of payments in the coming years are: first and foremost, an increase in the domestic production of petroleum and petroleum products, fertilisers, steel, edible oils and non-ferrous metals. These account for nearly 60 per cent of our total imports. The Government has taken necessary action to step up production and investment in these and other critical areas.

15. We must also intensify our efforts at expanding the export base and creating conditions conducive to larger exports. Exports have increased by 15.4 per cent during the first 8 months of the financial year, which is encouraging. However, in several areas, particularly in our traditional exports, such as textile fabrics, jute and tea, we are facing unfavourable world market conditions. While sustaining exports of these and other traditional commodities, much greater effort is now needed to expand those exports for which world markets are growing. In recent years, our receipts from invisibles, particularly from remittances by non-residents of Indian origin, have shown a healthy growth. This has been a stabilising factor in our balance of payments, and we must continue to provide adequate facilities for growth of receipts from this source.

16. The past two years have been years of crisis management and recovery. It is a measure of our success that the economy is now back on the rails. This provides us an opportunity to initiate further efforts for moving the economy forward and to achieve the necessary medium term adjustment. The objective of policy in 1982-83 will be to maintain the momentum of growth and to make an all out effort to achieve the social and economic objectives of the Sixth Plan. This would call for larger investments, and a relentless pursuit of goals of higher productivity, efficiency and reduction in disparities. This is the message of the revised 20-Point Programme. The Programme identifies the areas of special thrust in which there must be no compromise on performance.

17. The tasks that lie ahead are not easy. Hon'ble Members well aware of the evolving geo-political situation in our region and the difficult environment in which we are functioning. While we strive to resolve the situation in a spirit of goodwill, we have to take all necessary steps to safeguard the security of the nation. This burden, which is not of our seeking, will involve sacrifices on the part of our people.

18. In the international economic sphere, there is a rising trend towards protectionism which inhibits access to markets abroad. The environment for economic co-operation has also deteriorated, and the flow of concessional resources is likely to be less than envisaged earlier. In concert with other developing countries, we must continue to press for reforms in the international economic order and to reverse these disquieting trends. However, prudent management of the economy requires that due account is taken of the present international situation in devising our economic policies.

19. The investment requirements of the economy are large and brook no delay. It is essential that we now make a determined effort to mobilise more resources for investment. Maintenance of a non-inflationary environment requires that additional resource mobilisation represents real savings in the economy. However, adequate resources for further investment in new capacities will not be forthcoming unless we also take action to utilise the existing capacities fully. I am sure that this House will share my hope that all sections of the community would do their utmost to make this Year of Productivity a success. On its part, the Government would endeavour to provide due encouragement to promote this objective.

20. Mobilisation of resources in a non-inflationary way must be a multi-pronged effort. It is necessary to make appropriate adjustments in taxation and to ensure better tax collection. The pernicious growth of black money in the economy has been a major source of concern to the Government and Parliament. Various economic offences have seriously eroded our development efforts. In the past, we took a series of measures to fight against this menace. Unfortunately, this thrust was diluted during the period when we were out of office. I can assure the Hon'ble Members that our commitment to eradicate all economic offences is firm and uncompromising. I am taking steps to ensure that the provisions of law are applied vigorously and effectively to combat economic offences.

21. We must also continue to adjust administered prices in line with economic costs. Uneconomic pricing policies in the public sector and in high priority industries result in erosion of resources for further investment and lead to malpractices by unscrupulous traders. Price adjustments carried out in the last two years have amply demonstrated the important role of appropriate pricing policies in ensuring viable operations, generating additional resources and reducing the scope for generation of black money.

22. One of the strengths of our economy is the fairly high rate of savings. Most of these savings occur in the household sector. We need to ensure that savers have an adequate incentive to hold their savings in financial instruments. This could play a significant role in providing more resources for investment. Over the past two years, several steps have been taken in this direction. This thrust should continue.

23. In order to mobilise private savings for public use, the Government has decided to issue two new savings instruments. The first is a Social Security Certificate which has been specially designed for the small savers. Under this scheme, an individual between the age of 18 and 45 can invest upto Rs. 5000, which will triple in 10 years. The certificate will also provide social security to his family. In the case of investor's demise, his nominee or legal heir will become immediately entitled to the full maturity value of the certificate. The details of the scheme will be announced separately. I trust that this National Savings instrument will prove particularly attractive to large numbers in rural areas, and persons of small means everywhere.

24. The second instrument is the Capital Investment Bond which is designed to attract a larger flow of private savings for public sector investment. These bonds will have a maturity of ten years and carry an interest rate of 7 per cent free of income-tax. They will also be exempt from wealth tax, and upto Rs. 10 lakhs in the case of their first holder, from gift tax. Purchasers will have to duly account for these investments.

25. The rate of savings that we have been able to achieve is a tribute to the habits of thrift and good sense of our people. I have no doubt that they will take full advantage of the new opportunities and incentives that are being given to promote savings.

26. Remittances are an important source of foreign exchange for the country. They are also a manifestation of the close cultural and family ties that exist between the people of this country and the people of Indian origin abroad. In order to further encourage the flow of funds from this source, it has been decided to improve the facilities available to non-residents.

27. Any investment, without repatriation rights, made by non-residents of Indian origin, so long as it is not for transactions in commercial property and land, will be treated on the same footing as investments of resident Indian nationals. They will be allowed to invest, with repatriation rights, in any new or existing company up to 40 per cent of the capital issued by such company. They can now purchase shares of companies quoted on the stock exchanges subject to specified limits. The interest rates on new deposits of maturities of one year and above held in non-resident external accounts will carry interest of 2 per cent above the rates permissible on local deposits of comparable maturities. Gifts made in India out of deposits in these external accounts will be free from gift tax. The non-residents can also invest in the 12 per cent 6-year national savings certificates which, for them, will be free from wealth, income and gift taxes. Facilities for investment in non-resident external accounts and in Indian companies will be extended to companies, partnership firms, trusts, societies and other corporate bodies owned, to the extent of at least 60 per cent, by non-residents of Indian origin.

28. I shall now turn to the Revised estimates for 1981-82 and the Budget estimates for 1982-83.

Revised Estimates for 1981-82

29. I am happy to inform the House that there has been an all round improvement in revenue receipts during 1981-82. It is gratifying that despite significant tax concessions given in 1981-82 Budget, the receipts from income-tax are likely to be Rs. 1,520 crores as against the Budget estimates of Rs. 1,444 crores. Similarly, the receipts from corporation tax are likely to go up from Rs. 1,690 crores in Budget estimates to Rs. 1,962 crores in the Revised estimates. This increase is due to higher profits accruing to Oil and Natural Gas Commission and Oil India following the increase in the prices of crude effected last July. The receipts from customs duties are also expected to go up from the Budget estimates of Rs. 3,833 crores to Rs. 4,140 crores in the Revised estimates.

30. As regards Union excise duties, the House will be happy to note that they are expected to go up from Rs. 7,117 crores to Rs. 7,501 crores i.e. Rs. 384 crores more. This is clearly indicative of the marked growth in industrial production in the current year. The gross tax revenues are now estimated to be Rs. 15,754 crores compared with Rs. 14,668 crores in

the Budget estimates. After deducting the States' share of various taxes, net tax revenue of the Centre is estimated to be Rs. 943 crores more than the Budget estimate of Rs. 10,537 crores.

31. Non-tax revenues and capital receipts are also estimated to show an improvement of Rs. 579 crores over the Budget estimate of Rs. 12,795 crores. Market borrowings and small savings collections would be higher by Rs. 100 crores and Rs. 50 crores, respectively. The receipt from Special Bearer Bonds amounted to Rs. 875 crores in the current year against the Budget estimate of Rs. 800 crores. In addition to these receipts, there would be an increase of Rs. 200 crores in the recoveries of ways and means advances from State Governments, and of Rs. 117 crores in recoveries of technical credits under rupee trade agreements.

32. On the expenditure side, total budget support for the Plan is estimated to go up to Rs. 10,394 crores as against Budget estimates of Rs. 9,771 crores. The Central assistance for State and Union Territory Plans, including the programmes of Rural Electrification Corporation, is being stepped up by Rs. 156 crores. A large part of this increase is on account of higher advance Plan assistance to those States which have suffered from drought.

33. In the Central Plan, outlays for railways and coal have been increased by Rs. 157 crores and Rs. 105 crores respectively. Considering the growing pace of disbursements of Agricultural Refinance and Development Corporation, Industrial Development Bank of India and other financial institutions, additional Plan support of Rs. 389 crores is being provided to them in the current year. In view of the erosion in the internal resources of the Posts and Telegraphs Department, a higher budgetary support of Rs. 173 crores is being provided. On the other hand, shortfalls are anticipated in Plan expenditure in certain other sectors. On the whole, the budgetary support for the Central Plan is estimated to go up by Rs. 467 crores in the Revised estimates.

34. The Budget estimates provided for non-Plan expenditure of Rs. 15,100 crores. This expenditure will also be higher in the current year due to several reasons. The provisions for defence expenditure is being increased from Rs. 4,200 crores to Rs. 4,600 crores. Similarly, the provision for non-Plan loans to State Governments is being increased from Rs. 1,296 crores to Rs. 1,591 crores. This is mainly due to larger share of States out of collections from national small savings, and higher ways and means advances which, of course, are being recovered during the course of the year itself. The provision for food subsidy is being increased from Rs. 650 crores to Rs. 700 crores, subsidy on controlled and handloom cloth from Rs. 106 crores to Rs. 172 crores and the provision for cash compensatory support and market development for exports from Rs. 390 crores to Rs. 477 crores. Provision for technical credits under rupee trade agreements has also to be increased from Rs. 50 crores to Rs. 175 crores. A provision of Rs. 91 crores has been made in the Revised estimates for contributing India's share to the increased capital of the International Bank for Reconstruction and Development. Taking these and other variations into account, non-Plan expenditure in the Revised estimates is placed at Rs. 16,160 crores.

35. The total expenditure is estimated to be Rs. 26,554 crores in the Revised estimates compared with Rs. 24,871 crores in the Budget estimates. As against this, the total receipts are now estimated at Rs. 24,854 crores compared with Budget estimate of Rs. 23,332 crores. Thus, the current year is expected to close with a deficit of Rs. 1,700 crores, against the Budget estimate of Rs. 1,539 crores.

Budget Estimates for 1982-83

36. The Budget estimates for 1982-83 would show that I have given the highest priority to increasing the Plan outlay. The improvement in the economic situation in the last two years gives us an opportunity to make a major thrust towards achieving the goals of the Sixth Plan. I am providing for an outlay of Rs. 11,000 crores for the Central Plan in 1982-83. In making sectoral allocations, I have tried to emphasise the programmes for the uplift of the poor as enumerated in our 20-Point Programme as well as the investment needs of the infrastructure sectors.

37. The next year's Central Plan represents an increase of 27.6 per cent over the Plan outlay of Rs. 8,619 crores in the 1981-82 Budget estimates. This, Hon'ble Members will no doubt appreciate, is a very large increase considering, particularly, the commitments needed for safeguarding national security.

38. The Central Plan will be financed by a budgetary support of Rs. 7,343 crores and internal and extra-budgetary resources of Rs. 3,657 crores. The internal and extra-budgetary resources of public sector enterprises would thus account for 33.2 per cent of the Plan outlay as against 26.8 per cent in the previous year.

39. The total of Plan outlays for 1982-83 of the States and Union Territories, including a provisional outlay for West Bengal, is placed at Rs. 10,137 crores. This represents an increase of 14.4 per cent over the outlay of Rs. 8,860 crores in 1981-82. Central assistance for the Plan of the States and the Union Territories will be Rs. 4,002 crores compared with Rs. 3,462 crores in Budget estimates for 1981-82. Taken together, the Plan outlays of the Centre, States and the Union Territories for 1982-83 will be Rs. 21,137 crores, an increase of 21 per cent, over Rs. 17,479 crores in 1981-82.

40. In line with the Sixth Plan strategy, substantial increases in outlays are envisaged in crucial sectors of the economy. In respect of crude petroleum, there has already been a substantial expansion of output in the current year. With a view to sustaining the tempo of increased production, the outlay for this sector, including refineries and petrochemicals, has been fixed at Rs. 2,045 crores 1982-83, which represents an increase of 90 per cent over the current year. The outlay for coal is being increased to Rs. 877 crores as against Rs. 578 crores in 1981-82, an increase of 52 per cent. In the power sector, the outlay in the Central Plan is Rs. 929 crores compared with Rs. 721 crores in 1981-82. Taken together, the outlay for the energy sector, is 62 per cent higher than the current year, and constitutes 34 per cent of the Central Plan outlay.

41. The new Central power projects include installation of additional capacity of 1000 MW each at the Korba and Ramagundam super-thermal power stations. The total outlay for the power sector in the State and Central Plans taken together is Rs. 3,977 crores compared with Rs. 3,226 crores in 1981-82. Additional generating capacity of 3500 MW is expected to be commissioned during 1982-83.

42. The revised 20-Point Programme calls for intensified effort in a number of areas, which are vital for the development of the economy and for the welfare of our people, especially the weaker sections of the society. Effective implementation of this programme will be a step forward towards the realisation of our goal of social justice. This will call for concerted efforts at all levels. In 1982-83, higher outlays have been provided for several areas emphasised in the 20-Point Programme:

— a provision of Rs. 2,133 crores has been made for irrigation and Command Area Development in the Central and State Plans as against a provision of Rs. 1,830 crores in 1981-82;

— the outlay for agriculture in the Central and State Plan has been raised to Rs. 1,202 crores from Rs. 1,047 crores in 1981-82, including provisions for pulses, oilseeds and dry land farming;

— a provision of Rs. 190 crores has been made for the Integrated Rural Development Programme in the Central sector compared with Rs. 145 crores in 1981-82, an increase of 31 per cent. This would be matched by an equivalent provision by the States. Each block will receive Rs. 8 lakhs compared with Rs. 6 lakhs in 1981-82. With this provision more than three million rural families are expected to be assisted in 1982-83;

— the provision in the Central Plan for the National Rural Employment Programme is also being increased to Rs. 190 crores. This amount too is to be matched by an equal provision by the States. This programme is expected to generate employment of about 350 million man-days in rural areas besides creating durable community assets:

— Central assistance for the Special Component Plans for Scheduled Castes has been raised to Rs. 120 crores from Rs. 110 crores in 1981-82. This will be supplemented by a Central investment of Rs. 13.5 crores in the Scheduled Castes Development Corporations, with a contribution of the same order by the States. The Tribal Sub-Plan will also have a higher outlay of Rs. 95 crores in 1982-83;

— the outlay for the Centrally sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme is being increased to Rs. 127.5 crores to supplement the State Plan outlay of Rs. 273 crores. This will cover an estimated 45,000 problem villages;

— a provision of Rs. 74 crores is being made for house sites for rural landless persons and Rs. 29 crores are being provided for environmental improvement of slums in the State Plans;

— an outlay of Rs. 354 crores is planned for rural electrification. About 25,000 villages will be electrified and 4.25 lakh pumpsets energised in 1982-83;

— a provision of Rs. 5 crores has been made to facilitate setting up of 75,000 biogas plants, compared with 35,000 in 1981-82. Likewise, the Social Forestry Scheme is being expanded to cover 4 lakh hectares in 1982-83. Apart from providing much needed fuel wood, these afforestation programmes would help prevent soil erosion and restore the ecological balance.

— the outlay for family planning is being increased to Rs. 245 crores compared with Rs. 155 crores in 1981-82. In view of the crucial role which village health guides can play in the family planning movement, the Centre has decided to fund the Village Health Guide Scheme fully;

— a provision of Rs. 120 crores has been made in the Central Plan for health care. This will substantially augment universal primary health care facilities, and accelerate national programmes for control of leprosy, T.B. and blindness, with special emphasis on early detection and treatment. A provision of Rs. 82 crores has been made in the Minimum Needs Programme of the States for expanding rural health services;

— programmes for welfare of women would have an outlay of about Rs. 16 crores in the Central Plan which would augment the State Plan provisions. Special importance is being given to the programme of functional literacy for adult women for which a provision of Rs. 4.6 crores is being made as against Rs. 3 crores in 1981-82;

— the integrated Child Development Services Programme is being expanded to 1000 projects by the end of the current Plan as against the earlier target of 600 projects. An additional 320 projects are proposed to be taken up in 1982-83;

— for the Adult Education Programme, the Central Plan provides an outlay of Rs. 14.25 crores in 1982-83. Major part of this expenditure is for the Rural Functional Literacy Project. In 1982-83, it is proposed to establish such projects in 75 additional districts

— the outlay for the development of village and small industries has been raised to Rs. 340 crores in the Central and State Plans as against Rs. 315 crores in 1981-82.

43. The Central assistance for development of hill areas has been raised to Rs. 112 crores as against Rs. 92 crores in 1981-82. The Government has also recently extended to all hill areas the liberalised pattern of Central assistance comprising 90 per cent grant and 10 per cent loan.

44. The Central Plan outlay for the transport sector, including railways, roads, ports and civil aviation is being stepped up to Rs. 1,757 crores from Rs. 1,535 crores in 1981-82. My colleague, the Minister for Railways has already informed the House about the Railways Plan for 1982-83. In order to remove congestion at ports, an intensive modernisation programme, including augmentation of container handling facilities and construction of additional berths, is being implemented.

45. A provision of Rs. 480 crores has been made in the Plan for 1982-83 for the various programmes of the Departments of Heavy Industry and Industrial Development, including Rs. 97 crores for the Khadi and Village Industries Commission. This also includes Rs. 84 crores for the three large paper projects at Tuli in Nagaland, and at Nowgong and Cachar in Assam. Hon'ble Members would be happy to know that the Nagaland Paper Project will be going into production shortly. Work on three public sector cement projects will be started in 1982-83. The total installed capacity for cement in the country is expected to go upto 38 million tonnes in 1982-83 as against 32 million tonnes in 1981-82.

46. The Plan outlay for steel for 1982-83 is Rs. 860 crores. This includes a provision of Rs. 250 crores for the Visakhapatnam Steel Plant. The first phase of 1.2 million tonnes capacity is expected to be completed by the end of 1985. The work of establishing transport and raw material linkages for the Vijayanagar Steel Plant project is on hand. The Plan also includes an outlay of Rs. 140 crores for the Orissa Aluminium Project.

47. For the chemicals and fertilisers sector, Rs. 507 crores have been provided, including Rs. 210 crores for the Thal-Vaishet project and Rs. 120 crores for the Hazira project.

48. The successful launching of satellites in 1981 bears testimony to the dramatic strides made by our country in space technology. As part of the space programme, the APPLE space craft was launched in June, 1981. This is being utilised for various experiments, such as national Television and Radio hook-up, digital communication, interconnection of computers and subscriber trunk dialling. A major objective of the Government is to harness science and technology to bring about social and economic change. An outlay of Rs. 184 crores has been provided for the Science and Technology sector in the Central Plan for 1982-83.

49. The Government attaches special importance to renewable energy sources. The Commission for Additional Sources of Energy has initiated several important R & D and demonstration projects in the areas of solar thermal, photovoltaic, wind, biomass and integrated energy systems. The Government has exempted the manufacture of solar energy devices from industrial licensing.

50. A notable achievement has been successful expedition to Antarctica by our scientists. Following the collection of poly-metallic nodules from the sea bed for the first time by our ships last year, it is proposed to undertake a detailed survey in the Indian Ocean. An allocation of Rs. 17 crores has been included in the plan of the Science and Technology sector for the recently created Department of Ocean Development.

51. While I have tried to contain non-Plan expenditure for the next year, certain increases have been unavoidable. Defence expenditure is estimated at Rs. 5,100 crores as against Rs. 4,600 crores in the Revised estimates for the current year. Hon'ble Members will, I am sure, agree with me that in view of the uncertain external environment, the requirements of national defence should be fully met.

52. The provision for non-Plan loans to State Governments including ways and means advances is estimated at Rs. 1,732 crores as against Rs. 1,591 crores in 1981-82. Due to increase in internal and external debt, which is utilised for funding development programmes, the provision for interest will go up from Rs. 3,200 crores in the Revised estimates to Rs. 3,800 crores in 1982-83. The provision for subsidies on account of food, fertilisers, and controlled and handloom cloth is Rs. 1,270 crores. A provision of Rs. 500 crores has been made for cash compensatory support and market development assistance for exports.

53. I am also providing a lump sum of Rs. 350 crores in 1982-83 for payment of additional instalments of dearness allowance and pension relief to Central Government employees. The Government has received representations from pensioners that they should be given some relief in view of the rise in prices. In the Budget last year, my distinguished predecessor had announced some benefits to pensioners. I now propose to give further relief especially at the lower

levels of pension. The minimum amount of pension plus relief will be increased to Rs. 150 per month. The minimum amount of family pension plus relief will also be increased to Rs. 140 per month. These measures will benefit about 7 lakh low paid pensioners, and 2 lakh family pensioners. I would like to add that about 85 per cent of the former category are retired Defence personnel. The House will agree with me that those who have devoted the best years of their lives to the defence of the country are deserving of whatever support we can give them.

54. The total non-Plan expenditure for 1982-83 is estimated at Rs. 17,874 crores as against Rs. 16,160 crores in the Revised estimates for 1981-82.

55. As regards receipts in 1982-83, the gross tax revenues at the existing rates of taxation are estimated at Rs. 17,614 crores compared with Rs. 15,754 crores in the Revised estimates. The States share of taxes in 1982-83 is estimated at Rs. 4,716 crores compared with Rs. 4,274 crores in the current year. The Centre's net tax revenue will, therefore, be Rs. 12,898 crores as against Rs. 11,480 crores in the current year.

56. The receipts from market loans are estimated as Rs. 3,200 crores compared with Rs. 2,900 crores in 1981-82. Small savings are estimated to yield Rs. 1,400 crores as against Rs. 1,300 crores in the Revised estimates. External assistance, net of loan repayments, is estimated at Rs. 1,669 crores as against Rs. 1,381 crores in 1981-82.

57. Taking into account these and other improvements in non-tax revenues and capital receipts, as well as the effect of changes in fare and freight rates of the Railways, and in the Posts and Telegraphs tariff to which I shall refer a little later, the total receipts for 1982-83 are estimated at Rs. 27,134 crores. The total expenditure is placed at Rs. 29,219 crores. The overall budgetary gap at the existing rates of taxation will thus be Rs. 2,085 crores.

PART B

58. Sir, before I present my tax proposals, I would like to indicate the broad objectives I have kept in view. While we take comfort in our success in reducing inflation, it is of the utmost importance that the Budget itself should not give rise to further inflationary expectations. Any large uncovered deficit beyond prudent limits is inherently inflationary. It also gives rise to adverse expectations with regard to the behaviour of prices. It is therefore my major concern to keep the budgetary deficit as low as feasible.

59. Another important objective is to avoid measures which would place undue burdens on the low income and middle income groups. These groups are the worst sufferers in times of inflation.

60. As I have already indicated, providing adequate incentives for increasing production and savings in the economy is a prime objective of this Budget. Larger savings and increases in productivity can significantly help moderate inflationary pressures and also generate resources for development. The buoyancy in revenue and the decline in the rate of inflation in the environment of strong agricultural and industrial growth in 1981-82 confirm this.

61. Sir, coming now to direct taxes, my first proposal concerns salaried taxpayers. There have been many representations that the income-tax exemption limit should be raised, taking account of increases in the cost of living. I cannot accept, as a principle, that income limits for exemption from tax should be fixed with reference to cost of living. Nevertheless, I believe some relief to salaried taxpayers within the lowest taxable slab would be appropriate. At present, salaried taxpayers are entitled to a standard deduction equal to 20 per cent of the salary, subject to a ceiling of Rs. 5,000. I propose to raise the rate of deduction from 20 per cent to 25 per cent, without disturbing the ceiling of Rs. 5,000. This will give a significant measure of relief of those with salaries upto Rs. 20,000. The loss of revenue would be Rs. 21.58 crores in 1982-83.

62. Another measure of relief seems deserved, for those at the end of their working lives. I propose to exempt from income-tax, subject to certain conditions, the encashment

benefit in lieu of unavailed earned leave given to employees when they retire.

63. Taxpayers who are not in receipt of house rent allowance are entitled to a deduction upto Rs. 300 per month in respect of the house rent paid by them. However, persons receiving house rent allowance are entitled to an exemption up to Rs. 400 per month in respect of the house rent allowance received by them. I propose to raise the monetary ceiling from Rs. 300 to Rs. 400 per month also for those who are not receiving house rent allowance.

64. The owner of a self-occupied house is entitled to a deduction, from the annual letting value of the house, of an amount equal to one-half of the annual letting value or Rs. 1,800 whichever is less. I propose to raise the monetary ceiling of Rs. 1,800 to Rs. 3,600.

65. The annual letting value of a newly constructed house let out on rent is reduced for tax purposes by an amount up to Rs. 2,400 in respect of each residential unit for a period of five years. With a view to providing a stimulus for construction of houses, particularly for persons with relatively lower incomes, I propose to raise the monetary limit of Rs. 2,400 to Rs. 3,600.

66. I propose to liberalise the scheme of deduction in respect of long-term savings such as life insurance, provident fund contributions, etc. A deduction of 100 per cent will be allowed in respect of the first Rs. 6,000 of the qualifying savings, plus 50 per cent of the next Rs. 6,000 of such savings plus 40 per cent of the balance. The monetary ceiling in respect of the savings qualifying for deduction is also being raised from Rs. 30,000 to Rs. 40,000. The higher monetary ceiling in respect of the qualifying savings in the case of authors, playwrights, artists, musicians, actors, sportsmen and athletes, is also being raised from Rs. 50,000 to Rs. 60,000. These incentives for larger savings will result in a revenue loss of Rs. 26.17 crores in a full year and Rs. 19.76 crores in 1982-83. It may be desirable in due course to provide a wider choice of eligible modes of savings to taxpayers. I therefore propose to extend the existing tax concession in relation to investment in notified Central Government securities.

67. I find that out of the new life insurance policies issued by the Life Insurance Corporation of India, nearly 15 per cent policies lapse before the end of the following year. Such a high volume of lapses shortly after the issue of the policies is a matter of concern. It also implies that the very purpose for which the tax concession is allowed in respect of premia on such policies, which is to promote long-term savings through life insurance, is frustrated. I propose, therefore, to provide that where a taxpayer discontinues a life insurance policy before premia for two years have been paid, no deduction will be allowed in respect of the premia if any paid under the policy and, if such deduction has been allowed, the same shall be withdrawn.

68. Under the existing incentives for stimulating savings and investment, income up to Rs. 3,000 from investment in specified financial assets, such as Government securities, units in the Unit Trust of India, bank deposits and shares in Indian companies is exempt from income-tax. In addition, income upto Rs. 2,000 from units in the Unit Trust of India is exempt from tax. I propose to raise the ceiling of Rs. 3,000 to Rs. 4,000 and the separate ceiling in respect of income from units, from Rs. 2,000 to Rs. 3,000. This measure will result in a revenue loss of Rs. 12.12 crores in a full year and Rs. 9.09 crores in 1982-83.

69. As a parallel measure, I propose to raise the ceiling of the value of investments in specified financial assets exempt from wealth-tax from Rs. 1,50,000 to 1,65,000. In addition, the separate exemption of Rs. 25,000 provided in respect of units in the Unit Trust of India is proposed to be raised to Rs. 35,000. The revenue loss will be Rs. 1.54 crores in a full year, but there will be no loss in 1982-83.

70. At present, taxpayers are allowed a deduction, in the computation of taxable income, of 50 per cent of amounts invested in equity shares of new industrial companies and

companies engaged in providing long-term finance for construction or purchase of houses for residential purposes. The maximum investment in a year qualifying for this deduction is limited to Rs. 10,000. With a view to encouraging larger investments in such companies, I propose to raise the monetary ceiling for investment to Rs. 20,000.

71. While I have given some relief to those in the lowest taxable income range, I consider that there is scope for more progression in the tax rates for high incomes. I accordingly, propose to modify the rates of personal taxation, so as to raise the rate of income-tax on the slab of Rs. 60,001 to Rs. 70,000, from 50 per cent to 52.5 per cent and on the slab of Rs. 85,001 to Rs. 1,00,000, from 55 per cent to 57.5 per cent. This would yield Rs. 3.24 crores in a full year and Rs. 2.43 crores in 1982-83.

72. Deduction of tax at source from dividends, interest on securities and other interest causes considerable inconvenience, and even hardship, to a large number of small investors whose taxable income is below the exemption limit. For the convenience of such persons, I propose to provide that income-tax shall not be deducted at source if the recipient furnishes a declaration to the payer of such income to the effect that his estimated total income of the relevant year will be below the exemption limit.

73. I also propose to provide that tax will not be deducted at source from interest paid on such securities of the Central Government or a State Government as may be notified by the Central Government in this behalf.

74. The tests of "residence" in India laid down for taxation purposes result in hardship to Indian citizens earning income in foreign countries who come to India for short spells. An individual is regarded as resident in India in a year if he stays here in that year for 30 days only, and also maintains a dwelling house here for 182 days or more. As this test causes hardship to persons working outside India, who come home even on relatively short visits, I propose to delete this test of residence.

75. Under another test, persons who have been in India for 365 days or more in the four years preceding the relevant year, become resident in that year by being in India for 60 days or more in that year. In the case of Indian citizens who are employed abroad and who come to India on leave or vacation, the period is 90 days. I propose to extend this benefit also to the self-employed and those in other occupations, irrespective of their avocation abroad or the nature of their visit to India.

76. Indian citizens who go abroad for purposes of employment are now chargeable to tax in India on their foreign income, if they have stayed in India for more than 60 days that year. I propose to liberalise the provision so that an Indian citizen who leaves India in any year for purposes of employment shall not be treated as resident unless he has been in India for 182 days or more in that year.

77. I will now come to some proposals regarding foreign exchange earnings. I propose to provide some tax relief to exporters whose export turnover for any year exceeds that of the immediately preceding year by more than 10 per cent. The tax relief, to be calculated at a specified percentage of such excess turnover, would be limited to 10 per cent of the income-tax otherwise payable on export profits. The rate at which the tax relief will be calculated and the goods qualifying for the purposes of this concession will be notified by the Central Government.

78. With a view to strengthening the competitiveness of our construction contractors who have undertaken projects outside India, I propose to exempt 25 per cent of the profits derived by them from such foreign contracts, subject to certain conditions.

79. With a view to augmenting the capital base of Indian banks engaged in banking operations in foreign countries, I propose to provide that those banks which are approved in this behalf by the Central Government would be entitled to a deduction upto 40 per cent of their income carried to a special reserve account.

80. Interest-tax levied under the Interest-tax Act forms an integral part of our credit policy. However, taking note of the escalation in costs of industrial projects, I propose to exempt scheduled banks from payment of interest-tax on the interest received by them on loans sanctioned in foreign currency for import of capital plant and machinery. With a view to improving the competitiveness of export of capital plant and machinery, I propose to exempt interest paid on credit sanctioned by scheduled banks for export of capital plant and machinery on deferred payment terms outside India.

81. Investment allowance at the higher rate of 35 per cent is granted in respect of machinery and plant installed for the manufacture of articles made with know-how developed in Government laboratories, public sector companies, recognised institutions and universities. This concession is available in relation to machinery and plant installed upto 31st March, 1982. I propose to extend this tax concession for a further period of five years.

82. Dividends received by a domestic company from an Indian company engaged exclusively or almost exclusively in the manufacture of specified articles are completely exempt from income-tax. Having regard to the importance of basic drugs, synthetic rubber and rubber chemicals (including carbon black), I propose to extend the benefit of this tax concession to dividends received from companies engaged in the manufacture of these articles as well.

83. At present, scheduled commercial banks are allowed a deduction in respect of provisions made by them for bad and doubtful debts relating to advances made by their rural branches. The deduction is limited to 1.5 per cent of the aggregate average advances made by the rural branches. In order to promote rural banking and to assist non-scheduled commercial banks operating in the rural sector, I propose to extend the benefit of this tax concession to them also.

84. Energy saving and protection of the environment are high priority areas. I therefore propose to allow depreciation at 30 per cent on devices and systems for energy saving, or for minimising environmental pollution or for conservation of natural resources. The list of the qualifying items will be notified in due course.

85. At present, taxpayers are entitled to 100 per cent deduction in respect of donations made to approved institutions engaged in carrying out programmes of rural development. I propose to extend this concession to donations made to approved institutions for use in programmes of conservation of natural resources.

86. Hon'ble Members will be happy to hear that I propose to place donations made to the National Children's Fund at par with donations made to other funds of national importance such as the National Defence Fund, the Jawaharlal Nehru Memorial Fund, and the Prime Minister's National Relief Fund.

87. I consider that some rationalisation of the taxation in respect of capital gains is desirable. In the case of non-corporate taxpayers, long-term capital gains up to Rs. 5,000 are deducted in full. Of the balance amount, a deduction of 25 per cent is allowed where the gains relate to lands and buildings and of 40 per cent where the gains relate to other assets. I propose to modify these provisions so as to relate the deduction to the period for which the capital asset has been held by the taxpayer, and allow a larger deduction in cases where the asset has been held for a longer period. The aggregate deduction in respect of capital gains relating to gold, bullion or jewellery will, however, be restricted to Rs. 50,000 only.

88. There is an acute shortage of housing, and house building activity has to be given impetus. With a view to providing an incentive to taxpayers who do not own a residential house, I propose to exempt from tax long-term capital gains arising from the transfer of other assets where the net consideration is invested by the taxpayer in a residential house.

89. At present, capital gains arising from the transfer of a house used for personal residence by the taxpayer are exempt from income-tax to the extent that such gains are utilised by the tax-payer for constructing or purchasing a house for purposes of personal residence within a specified period. These conditions often lead to hardship. I therefore propose to remove these restrictive conditions.

90. Charitable and religious trusts are required to conform to the investment pattern laid down in the Income-tax Act. Any trust which has not changed over to this pattern of investment will forfeit exemption from tax from the assessment year 1982-83. These trusts have been given adequate notice to change their investment pattern and, ordinarily, I would not have proposed any modification in these provisions. However, I find that the whole gamut of the provisions relating to charitable and religious trusts is under consideration by the Economic Administration Reforms Commission. As the Government would like to carefully consider the recommendations of the Commission in this matter, I propose to amend the relevant provisions so that such trusts do not forfeit exemption from income tax for the assessment year 1982-83.

91. My distinguished predecessor had made an announcement in the Lok Sabha on the 31st March, 1981 that the provisions of the Income-tax Act relating to the investment pattern of trust funds would be modified, so as to permit charitable and religious trusts or institutions to invest the trust funds in immovable properties as well. I am proposing an amendment of the relevant provisions of the Income-tax Act to fulfil the assurance given by him.

92. While the levy of wealth-tax on agricultural property was discontinued by the Finance (No. 2) Act, 1980, owners of tea, coffee, rubber and cardamom plantations continue to be chargeable to wealth-tax. Our experience is that the valuation of agricultural land forming part of such plantations leads to administrative difficulties, complaints of harassment and litigation. The yield from this levy is also insignificant. I, therefore, propose to discontinue the levy of wealth-tax on such plantations as well.

93. The value of tools and instruments necessary to enable the taxpayer to carry on his profession or vocation is exempt from wealth-tax upto an aggregate amount of Rs. 20,000, which appears inadequate. I propose to raise it to Rs. 50,000. I also propose to raise, from the present Rs. 30,000 to Rs. 75,000, the ceiling of the value of conveyances, including motor cars, for the purpose of exemption from wealth-tax.

94. Stamp duty paid on an instrument relating to the gift of any property is allowed as a deduction from the gift-tax payable by the tax-payer in cases where the amount of gift-tax exceeds Rs. 1,000. I propose to allow the benefit of this deduction even where the gift-tax payable does not exceed Rs. 1,000.

95. The Hotel-receipts Tax Act, 1980 provides for the levy of a tax on the gross receipts of luxury hotels. As the levy of this tax may adversely affect the flow of foreign tourists into India, I propose to discontinue this levy in relation to the chargeable receipts of such hotels accruing or arising or received by them after the 27th February, 1982. The revenue loss would be about Rs. 6 crores.

96. The other proposals in the field of direct taxes are of relatively minor importance. I would, therefore, not like to take up the time of the House by referring to them here.

97. Hon'ble Members would have noted that in the direct tax proposals I have set out, I have endeavoured to preserve stability in the tax system, while providing substantial incentives for savings. I have also rationalised the capital gains tax and provided some concessions where necessary.

98. Mr. Speaker, Sir, I now turn to the area of indirect taxes. Taking customs duties first, my principal proposal is with regard to auxiliary duties of customs. This levy, which has been imposed on an annual basis since the 1973 Budget, is proposed to be continued during 1982-83. The balance of payments position has been under pressure in recent times and will continue to be so for some time to come. However, a liberalised regime of imports has been a feature of our economic policies. This will be continued in order that investment and production, particularly in essential and priority

sectors, are not hampered or slowed down. There is no strong reason, however, why those who have access to imports in a difficult situation should grudge to pay a little more. I accordingly propose to increase the rates of auxiliary duties by 5 percentage points on all categories of imports, with some exceptions.

99. I am excluding from the proposed increase in auxiliary duty essential items like crude petroleum, bulk petroleum products, such as kerosene and high speed diesel oil, and some other items on which import duty rates have adjusted in the recent past on price parity considerations. Fuller details of these proposals are available in the Budget papers.

100. My proposals relating to auxiliary duties of customs are expected to yield an additional revenue of Rs. 290 crores.

101. In the light of the present market conditions, and the need for encouraging a few selected industries, it is necessary to effect certain changes in the basic customs duties. I propose to raise the basic customs duty on cork and cork articles from 40 per cent to 60 per cent ad valorem; on certain categories of dyestuffs, from 60 per cent to 100 per cent ad valorem; and on certain other categories of dyestuffs, pigments and colours and paints and varnishes, from 100 per cent to 150 per cent ad valorem. I also propose to increase the basic customs duty on certain items of iron and steel, such as melting scrap of stainless steel and heat-resisting steel, and certain categories of alloy steel excluding stainless steel and heat resisting steel, from the existing levies to 60 per cent ad valorem. The effective rate of basic customs duty on copper pipes and tubes, blanks and hollow bars of prescribed specifications will be increased from 40 per cent to 60 per cent ad valorem. The basic customs duty on polyester chips is being increased from 100 per cent to 140 per cent. These proposals are likely to result in additional revenue of Rs. 42 crores.

102. It may be recalled that in the last Budget, an effective customs duty of 15 per cent ad valorem was imposed on imported newsprint on which there continues to be large foreign exchange outgo. The Government has received representations against this levy. I propose to convert the ad valorem levy to a specific total levy of Rs. 825 per metric tonne so as to obviate automatic increase in its incidence on account of rising international prices. There will be no revenue loss.

103. The indigenous zinc and lead industries are facing difficulties owing to escalation of input costs, particularly of imported concentrates. In order to enable them to increase their capacity utilisation, I propose to reduce the total customs duty incidence on imported zinc concentrates from 50 per cent to 15 per cent ad valorem and that on lead concentrates from 50 per cent to 5 per cent ad valorem. Simultaneously, I propose to increase the customs duty on imported zinc metal from 50 per cent ad valorem to 60 per cent ad valorem. In order partly to offset the revenue loss, I propose to increase excise duties on indigenously produced zinc metal, zinc scrap and zinc products by Rs. 715 per metric tonne and that on lead metal and scrap by Rs. 374 per metric tonne. The excise duty on zinc pipes and tubes will go up from 38.5 per cent to 49.5 per cent ad valorem. These measures, taken together, would result in an overall loss of about Rs. 41 lakhs.

104. With a view to improving the competitive position of Indian chromite ore in the context of falling prices in the export market, I propose to convert the existing specific rates of export duty applicable to different grades of the ore and concentrates to an ad valorem duty of 10 per cent. The revenue sacrifice is of the order of Rs. 1 crore.

105. I also propose to fully exempt two fertilizers—Calcium Ammonium Nitrate and Ammonium Sulphate from customs duties. The import duty on internal combustion engines and non-inter-changeable parts of such engines for manufacture of power tillers is also proposed to be reduced from 125 per cent to 50 per cent.

106. I propose to fully exempt 10 more bulk drugs imported for manufacture of life-saving drugs and medicines. Details are being notified.

107. During the past few years, the Government has been using the fiscal mechanism for accelerating the growth of the

electronics industry. As a further step in this strategy, I propose to raise the basic customs duty on electronic items such as computers, calculating machines, accounting machines, cash registers and certain electronic sub-assemblies from the existing levels of 40, 50 and 60 per cent to 100 per cent ad valorem. On the other hand, I propose to extend the scope of the present import duty concessions to cover 45 new items of capital equipment and 13 new items of raw materials and components used by the electronics industry. The customs duties leviable on these items are proposed to be reduced from the respective existing rates to 35 per cent ad valorem in the case of machinery and instruments and to 55 per cent ad valorem in the case of raw materials and components. The net revenue gain from these proposals is Rs. 13 crores.

108. Representations have been received that it is not always possible for units in the Free Trade Zones to export their entire production, and that a provision should be made to allow a proportion of the goods manufactured in these Zones to be cleared into the domestic tariff area. It has been decided, subject to certain conditions to allow such removals upto 25 per cent of the production of a unit for sale or use within the country on payment of appropriate duties. Provision is being made in the Finance Bill to amend the Customs and Central Excise Acts for the purpose.

109. On the Central excise side, the levy of special duties of excise is proposed to be continued at the existing rates during the year 1982-83. The existing exemptions from the special duty are also proposed to be continued.

110. As I said earlier, my basic approach has been that additions to revenue from Central excise duties should essentially come from increased production. I am also avoiding recourse to measures which could affect retail prices over a wide spectrum of goods. I have accordingly selected only a very few items for increased taxation. In selecting these items, I have kept in view the demand and supply situation which has resulted in undue profits to trading channels, the scope for subjecting certain articles of elite consumption to a higher rate of tax, and the need to restructure the excise and customs duties applicable to certain basic industries.

111. The Government has decided to introduce a scheme of 'levy' and 'free' sale of cement, and a dual pricing policy based on this concept. Details of the new scheme are being notified by the Government separately. There has been no increase in the low level of basic excise duty on cement since January, 1977, even though thereafter the price of cement has increased very substantially. I propose to increase the total excise duty on ordinary portland cement, portland pozzolana cement, blast furnace slag cement and masonry cement, from Rs. 71.50 to Rs. 135 per metric tonne. The more expensive special varieties of cement will be subject to higher rates of duty. The effective total excise duty on cement produced in mini cement plants is proposed to be fixed at Rs. 100 per tonne. I also propose to impose a basic customs duty of 10 per cent ad valorem on imported cement together with full countervailing duty. No auxiliary duty would be leviable on imported cement. These proposals will give additional revenue of Rs. 158.73 crores on the Central excise side and Rs. 39.60 crores on the customs side. The impact of the proposed increase in excise duty per bag of cement of 50 kilograms would work out to Rs. 3,175.

112. In the recent past, certain expensive electronic goods favoured by the affluent are being produced in increasing quantities. These are now subjected to a very low incidence of duty at 8 per cent ad valorem under Item 68 of the Central Excise Tariff. I now propose to carve out new entries in the Excise Tariff, and subject video cassette recorders and reproducers, television cameras and video cameras, and similar goods to a basic excise duty of 25 per cent ad valorem. Blank and recorded video and audio tapes of the spool and cassette types, as also video discs, are also proposed to be subject to a basic duty of 25 per cent ad valorem. Recordings which are not for commercial purposes will be exempt. I also propose to levy basic duty at a higher rate of 40 per cent on electronic machines for games of skill or chance, including those used for television games and video games. These proposals would yield revenue of Rs. 3.83 crores.

113. Toilet preparations not containing alcohol are liable to Central excise duty at the basic rate of 100 per cent ad valorem whereas those containing alcohol attract duty under the Med-

cial and Toilet Preparations (Excise Duty) Act at only 60 per cent ad valorem or Rs. 13.20 per litre of pure alcohol content, whichever is higher. Some misuse because of these differential rates has come to notice. I, therefore, propose to raise the alternative ad valorem rate to 100 per cent ad valorem so as to place both categories of toilet preparations more or less at par. The revenue yield from this measure is expected to be Rs. 2.3 crores and would accrue mostly to the States.

114. Hon'ble Members may recall that the Textile Policy Statement of March, 1981 envisaged a review of fiscal levies on man-made fibres and yarn. While cotton will continue to enjoy the predominant position in textiles, it is necessary to encourage increased consumption of blends of cotton and man-made fibres and yarns, if we are to achieve the Plan target of even a modest increase in the per capita availability of cloth. For some time past, blended fabrics containing polyester fibre in proportions too small to impart the requisite durability and easy-care properties to the fabrics are flooding the market with stampings thereon which would mislead the public. From the point of view of better utilisation of polyester fibre, it is necessary to encourage blends of desirable proportions and discourage blends which do not really serve the intended purpose. I therefore propose to make certain changes in the fiscal levies applicable to man-made fibres and yarns. I propose to increase the duty on blended cotton yarn and cellulosic spun yarns containing up to one-sixth by weight of polyester fibre from the existing average total incidence of Rs. 1.63 per kilogram to Rs. 7.5 per kilogram. The total incidence on such blended yarns containing more than one-sixth but less than 50 per cent of polyester fibre, which seem to be desirable blends in Indian conditions, is proposed to be reduced from Rs. 22.50 per kilogram to Rs. 11.25 per kilogram. Similarly, the incidence on blends containing 50 per cent or more but less than 70 per cent of polyester fibre is being reduced from Rs. 30 per kilogram to Rs. 22.50 per kilogram. There will be no change with regard to blends containing 70 per cent or more of polyester fibre.

115. It is proposed to increase the total incidence of Central excise duty on acrylic fibre from Rs. 12.50 to Rs. 17.50 per kilogram and simultaneously to reduce the countervailing duty on imported fibre from Rs. 37.50 to Rs. 30 per kilogram.

116. Turning to viscose staple fibre, the excise duty is being raised from Rs. 3.125 per kilogram to Rs. 4 per kilogram and the duty on polynosic and high wet modulus fibres is being reduced from Rs. 5 to Rs. 4 per kilogram.

117. Acetate filament yarn which is used in the decentralised sector is not produced in adequate quantities in the country. It is proposed to reduce the customs duty on it from 125 per cent to 20 per cent ad valorem so as to facilitate imports of this yarn.

118. I do not propose to change the exercise or basic customs duty rates applicable to other fibres such as acetate fibre and polyester fibre and other filament yarns such as viscose, nylon and polyester filament yarn.

119. These proposals would result in a net loss of Rs. 13 crores on the Central excise side and a gain of Rs. 12.94 crores on the customs side.

120. At present, there is no basic excise duty leviable on man-made fabrics, the incidence of such duties having been shifted to the fibre and yarn stages. These fabrics attract only additional excise duties in lieu of sales tax. While the present rate structure is progressive on fabrics having ex-factory price upto Rs. 10 per square metre, it is not so in respect of the higher priced fabrics since the duty applicable to them is a uniform 54 per cent ad valorem. There are very high-priced fabrics in the range, catering to affluent consumption, and these fabrics can well bear a moderate increase in duties. I therefore propose to introduce further progression in the rate structure in such a way that fabrics having ex-factory prices of more than Rs. 20 per square metre would attract duty at 74 per cent ad valorem. The additional revenue from this proposal is estimated at Rs. 35 crores, which will go to the States. The proposal would also be a step towards fulfilment of the Centre's commitment to the States to increase the overall incidence of additional excise

duties in lieu of sales tax, as a percentage of the value of clearances. I am sure that Parliament and the States would whole-heartedly welcome this step.

121. The overall effect of the duty changes on blended fabrics containing cotton, cellulose and polyester would be a decrease in the price of desirable blends and an increase in the price of the other less desirable blends.

122. I have included in the Finance Bill some provisions designed to achieve simplification and greater clarity in the tariff nomenclature and thereby minimise the scope for classification disputes. These measures are not designed as revenue raising exercises, but because of the changes in classifications, some revenue will accrue. The proposals cover, among others, major petroleum products, artificial and synthetic resins and plastic materials.

123. I also propose to rationalise and restructure the tariff relating to paper and paper boards, the primary objective being to exempt small scale paper converters from payment of excise duty and to release them from excise control. In order to recoup the consequent loss in revenue, I propose to raise the basic excise duty on industrial varieties of paper and paper boards by a small margin of 2-1/2 per cent ad valorem. However, certain converted papers of high value-added categories are proposed to be subject to basic excise duty at 32-1/2 per cent ad valorem. Similarly, specified articles made of paper and paper board are proposed to be brought within the purview of the tariff item but effectively restricting the levy to printed cartons and printed boxes.

124. In recent years, the scheme of input excise duty relief has been extended to cover certain specified industrial products. I propose to further extend input duty relief in respect of synthetic rubber, carbon black and rubber processing chemicals going into the production of tyres. To make up for the revenue loss I propose to raise the duty leviable on tyres from a total of 60.5 per cent to 66 per cent ad valorem. While tyres for tractors and scooters will also enjoy the benefits of the input duty relief, I do not propose to increase the final duty rates on them. As this is intended to be a balancing exercise, no credit for additional revenue is being taken.

125. As the House is aware, the administered price of aluminium metal is revised periodically, keeping in view escalations in input costs. In order to contain the incidence of excise duty, it is proposed to levy duty at specific rates. The rates would be Rs. 3.085 on electrolytic grade ingots, Rs. 3.125 on billets, Rs. 3.330 on wire rods produced by primary producers and Rs. 3.280 on wire bars. There would be no change in the rates of countervailing duties. The proposal will give some relief to the finances of State Electricity Boards.

126. As an anti-avoidance measure, I propose to add to the present ad valorem levy on flat glass, a specific levy at the rate of Rs. 5.50 per millimetre thickness per square metre. Effective rates of duty are being prescribed at lower levels for different categories of flat glass.

127. The Government has received a large number of representations alleging malpractices in the birli industry, on account of the present differential rates of excise duty applicable to branded and unbranded biris. Many State Governments and Associations have urged that this distinction should be done away with. A suggestion to the same effect has also been made in a recent meeting of Labour Ministers. Taking note of these points, I propose to do away with the existing duty differential and to subject both branded and unbranded biris to a uniform composite duty rate of Rs. 3.60 per thousand. Simultaneously, the existing quantum of unbranded biris eligible for duty free clearance is also being reduced from 30 lakhs to 20 lakhs in a financial year. This would still leave self-employed family units, petty shopkeepers etc. out of the tax net.

128. The general scheme of excise duty concession applicable to small manufacturers of 72 specified groups of commodities is being extended to manufacturers to asbestos fibre and yarn. Some misuse of the scheme with a view to avoiding excise duty on popular brands of aerated waters has come to notice. I therefore propose to take aerated waters out of

the scope of the general scheme and devise a new scheme for it. Essentially, small manufacturers who sell their products under their own brand or trade names would continue to enjoy the benefits available under the present scheme. However, manufacturers who produce and bottle aerated waters under brand or trade names in pursuance of agreements with the owners of such brand or trade names would not be eligible for the concession. This also is purely an anti-avoidance measure.

129. The general scheme referred to earlier seems to have been similarly exploited by certain small manufacturers of synthetic organic dyestuffs. Under the present scheme, clearances upto Rs. 7-1/2 lakhs are fully exempt and an additional Rs. 7-1/2 lakhs are subject to duty at 3/4ths of the duty rate applicable to the organised sector. In view of the relatively high rate of duty on dyestuffs and the fact that techniques of production of some dyestuffs are comparatively simple, it appears there has been a proliferation of small units with consequent deleterious effects on the quality, and also on the industry as a whole and on exports. I, therefore, propose to delete dyestuffs from the purview of the general scheme. Under a new scheme which is being announced in respect of dyestuffs, very small manufacturers whose clearances do not exceed Rs. 1 lakh per annum will be fully exempt from excise duty. In the case of other small manufacturers, clearances upto Rs. 15 lakhs of dyestuffs will be subject to 50 per cent of the duty applicable to the organised sector. All manufacturers will be brought under excise control. The monetary content of the present scheme of relief is, by and large, maintained under the new scheme.

130. At present, certain specified consumer electronic goods manufactured in the small sector attract duty rates lower than the normal rates. To restrict this duty concession to genuine small manufacturers, it is proposed to restrict the scheme of duty exemption to manufacturers with total annual turnover not exceeding Rs. 2 crores.

131. With regard to the match industry, I do not propose to disturb the existing duty structure. Small manufacturers whose clearances have not exceeded 150 million matches in the preceding financial year would continue to be eligible for the concessional rate of duty of Rs. 1.60 per gross boxes on clearances upto 120 million matches in the financial year. The concession will not be available if the matches are marketed under the labels of manufacturers who pay duty at Rs. 4.50 or Rs. 7.20.

132. As Hon'ble Members are aware, the Government has been using the excise duty mechanism as a powerful incentive for the growth of the cottage sector of the match industry. A number of manufacturers in the middle sector have, however, challenged in courts of law, the excise concession scheme for the cottage sector and obtained judgements in their favour. This may result in refund of substantial amounts of duty to the middle sector units. As the element of duty at the higher rate would have already been passed on to the millions of consumers, any refund of such duties would only result in unjust enrichment. A provision has been made in the Finance Bill to obviate this contingency.

133. There have been some disputes in the recent past regarding the determination of assessable values of excisable goods from a given cum-duty price, resulting in considerable litigation. This has resulted in locking up substantial amounts of revenue. It is proposed to suitably amend section 4 of the Central Excises and Salt Act to make it clear that in computing the amount of duty of excise deductible from the cum-duty price, the effective amount of duty of excise payable on the goods under assessment shall alone be taken into account. This amendment is being given effect to, retrospectively from 1st October, 1975.

134. It has been the long-standing practice to charge excise duty on goods used for captive consumption within the factory where they are produced. Some doubt had, however, been cast on this position as a result of judgements of some High Courts, which interpreted certain provisions of the Central Excise Rules to hold that duty could not be collected on such goods as they had not been 'removed' from the factory. A number of manufacturers have also obtained stay orders from courts based on the same grounds. The matter

has been taken up in appeal. Nevertheless, in order to place the position beyond doubt, the relevant Central Excise Rules have been suitably amended. A provision has also been included in the Finance Bill so that these amendments will have retrospective effect and the collections of duty made in accordance with the existing practice will also be validated.

135. As the House is aware, 1982 has been designated by the Prime Minister as the "Productivity Year". With the improvement in infrastructural facilities, it is hoped that industrial production would register further growth in the current year. The fiscal mechanism could be judiciously deployed in furthering this objective. With this in view, I propose to formulate a scheme of excise duty concession for increased production of goods during the period of 12 months commencing on the 1st March, 1982 and ending on the 28th February, 1983. The scheme would cover 38 tariff items including some basic raw materials, other important industrial inputs and certain finished products. Some of the items are caustic soda, fertilisers, synthetic resins, steel ingots and steel products internal combustion engines, wires and cables, two and three wheeled motor vehicles, light and heavy commercial vehicles, tractors, railway wagons, man-made fibres and filament yarn, tyres and writing and printing paper. A full list may be found in the Budget papers. The benefits of the scheme would accrue only in cases where the production in the 12 months period referred to above exceeds 110 per cent of the production during the base period, namely, the 12 months ending on the 28th February, 1982. The duty concession would be 1/5th of the total amount of duty paid on the excess production computed, as explained earlier, in respect of goods carrying basic excise duty of 20 per cent ad valorem or less, and 1/10th of the duty in other cases. The amount so computed for the whole period would be given as a credit which may be utilised for payment of Central excise duty during the financial year 1983-84.

136. The scheme will apply also to small scale manufacturers, who actually pay duty. It is proposed to ensure that those small scale units which are eligible for the benefits of the relevant excise duty concession schemes and are within the respective cut-off points during the year 1981-82, would continue to be eligible to the said benefits in 1983-84, even if they produce and clear goods in excess of the eligibility limits in the Productivity Year.

137. I am sure that industry will rise to the occasion and respond to this generous gesture of the Government and achieve new peaks of production. Since the Government would also be a beneficiary of the higher production in the shape of increased collection of excise duties, I do not propose to take any amount as revenue loss on account of the proposed concession.

138. I have already referred to the need to minimise the impact of my proposals on the middle and poorer sections of society. I propose to go further and give some concessions on articles of special interest to those sections. I propose to partially or fully exempt from excise duties several articles of common consumption. Some of these products are of interest to the student community, some are of general utility, yet others of interest to the disabled and one in the interest of horticulture. I propose to fully exempt from excise duty, pencils, erasers, pens including ball point pens and refills, laboratory glassware, enamelware, thermos flasks and parts, water coolers, candles, tooth brushes, spectacles and spectacle frames, one-day alarm clocks, domestic water filters, hand-pumps, Braille typewriters, invalid carriages and helmets. Further, I propose to reduce the basic excise duty on specified fruit and vegetable preparations from 15 per cent to 10 per cent ad valorem. I also propose to increase the present value limits of Rs. 15 per pair of footwear for eligibility to full duty exemption to Rs. 30 per pair. Lac is also being exempted. In order to reduce the packaging cost involved in the sale of milk in laminated paper packs, I propose to exempt from excise duty low density polyethylene film and paper to be used by the Indian Dairy Corporation for the manufacture of such paper packs. This measure should enable larger marketing of milk in paper packs which have a longer shelf life, and also help in the better utilisation of surplus milk produced in flush seasons.

139. At present, mopeds of engine capacity upto 75 cc bear a reduced rate of excise duty of 10 per cent ad valorem.

This fuel-saving personalised conveyance is becoming increasingly popular particularly in urban and semi-urban areas. I propose to extend the concession to models of engine capacity upto 100 cc which are expected to be more fuel-efficient.

140. I had referred earlier to certain adjustments of excise and customs duties consequent on a review of the fiscal levies on man-made fibres and yarn. The production of blended cloth in the handloom sector is at present around 12 million metres. In order to enable the handloom sector to register faster growth, I propose to fully exempt from excise duties polyester blended fabrics woven on handlooms from processing stage duties, if they are processed in factories set up by State Handloom Development Corporations or Apex Co-operative Societies approved in this behalf by the Central Government. This concession involves a revenue loss of Rs. 4 crores. I also propose to exempt metallised man-made filament yarn from the whole of the excise duty considering its use in saris and the like. The value of this concession is about Rs. 1 crore.

141. These excise duty concessions I have just referred to entail a total revenue sacrifice of Rs. 13.77 crores in a full year.

142. Where the changes are to be made by Notifications effective from 28th February, 1982, copies thereof will be laid on the Table of the House in due course.

143. My proposals will yield a net sum of about Rs. 196.18 crores from excise duties and Rs. 391.35 crores from customs duties. The yield from duties under the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act will be Rs. 2.30 crores in a full year. Taking all the proposals together, the net accrual to the Central exchequer in a full year will be Rs. 487.60 crores and that to the States will be Rs. 102.23 crores.

144. I now have something to say on behalf of my Hon'ble colleague, the Minister of Communications. As the House is aware, postal services have been extended over the years throughout the country. There are over 1,40,000 post offices. The service is highly employment intensive, with more than 5.6 lakh employees including extra-departmental staff. Salaries and wages therefore constitute a major part of the operating expenses of the Postal Department. The postal services are presently under-priced and the rates are inadequate even to meet the direct cost of several services. The grant of additional instalments of dearness allowance, and increases in other operating expenses, add significantly to these costs. A revision of tariffs for some postal services has therefore become unavoidable. Accordingly, it is proposed to raise the rate for printed post cards from 20 paise to 25 paise, letter cards from 25 paise to 35 paise and envelopes of the lowest

weight slab from 35 paise to 50 paise. There will be no increase in the rate of the ordinary post card which is generally used by the common man, even though this service involves an annual loss of about Rs. 20 crores. The tariff for book-post articles is also proposed to be raised from 25 paise to 30 paise. The postage for a registered newspaper has remained at the very low level of 2 paise for many years now. It is proposed to fix it at 5 paise for a single newspaper, with suitable adjustments for higher weight slabs. Even after this revision, the newspaper service will be subsidised to the extent of Rs. 7 crores a year.

145. A memorandum showing the proposed tariffs is being circulated along with the Budget documents. The changes would take effect from a date to be notified after the Finance Bill is passed by Parliament. The revisions proposed are estimated to yield an additional revenue of Rs. 35.33 crores in a full year and about Rs. 26 crores in 1982-83.

146. I had mentioned that the budgetary deficit at the existing rates of taxation would be Rs. 2,085 crores. The tax measures proposed now, taken together with the reliefs and concessions, are estimated to yield net additional revenue of Rs. 470 crores to the Centre and Rs. 63 crores to the States during 1982-83. Besides, the States will get an additional revenue of over Rs. 2 crores from the increase in the duty on medicinal and toilet preparations. I am taking credit for Rs. 250 crores as receipts from the Capital Investment Bonds which I referred to earlier. This would leave an uncovered deficit of Rs. 1,365 crores in 1982-83, which is substantially lower than the estimated deficit for the current year.

147. Mr. Speaker, Sir, I have set forth a framework of policies with a view to encouraging higher savings investment and production in the economy. Plan outlays are being stepped up substantially, particularly for sectors emphasized in the 20-Point Programme. Adequate provision has been made for national security. Despite these commitments, the budgetary deficit has been contained within reasonable limits. To achieve this, a measure of resource mobilisation was inescapable. I have, however, taken care to see that resources are raised without building new inflationary pressures. In particular, I have tried to avoid placing burdens on the low and middle income groups. The Budget constitutes a challenge to all those who are associated with the implementation of our development plan. It is an invitation to farmers, industry and labour for higher productivity; to the trading community for ensuring healthy marketing and distribution; and, indeed, to all our people, soldiers and civilians, to march forward shoulder to shoulder in the twin tasks of national development and defence.

148. Sir, I now commend the Budget to the House.

A. C. TIWARI, Jt. Secy.

